● वर्ष-4
● अंक-115
रायपुर, मंगलवार
24 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» मैं अध्यात्म की ओर बढ़ गई...

प्रदेश में 15,000 करोड़ का निवेश होगा

नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया संवाद

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक

नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं।उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा छत्तीसगढ़ की पहल की सराहना करते हुए निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री सेन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने नई औद्योगिक नीति की खासियतों को समझाते हुए निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लाभ बताए।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अहम बैठक में समरसता पर जोर

भारत जोड़ने की पहल

नई दिल्ली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली के उर्दू घर में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन मंच के आगामी 23वें स्थापना दिवस (24 दिसंबर) के उपलक्ष्य में किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने की। बैठक में मंच के सभी राष्ट्रीय संयोजक, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजक, सह संयोजक और वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य मंच की आगामी रणनीति तैयार करना और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना था। बैठक में शामिल प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद अफजाल, डॉ. शाहिद अख्तर, अबु बकर नकवी, विराग पाचपोर, डॉ. माजिद तालिकोटी, डॉ. शालिनी अली, शाहिद सईद, सैयद रजा हुसैन रिजवी, हाफिज साबरीन, इमरान चौधरी, फैज खान, और शाकिर हुसैन का उल्लेख हुआ।

बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर-

मस्जिद विवाद पर दिए गए बयान की जमकर सराहना की गई। मंच ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि भारत को मंदिर-मस्जिद विवादों में उलझने के बजाय विकास और समरसता पर ध्यान देना चाहिए।भागवत के बयान, जिसमें उन्होंने मंदिरों के नीचे मस्जिद खोजने की गतिविधियों को अनावश्यक बताया था, की प्रशंसा करते हुए मंच ने कहा कि यह विचार देश के 142 करोड़ लोगों के बीच भाईचारा और एकजुटता को बढ़ावा देता है। मंच ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इन मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने से बचें और समाज में शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

संभल और बांग्लादेश के मुसलमानों को संदेशः मंच ने संभल और बांग्लादेश के मुसलमानों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत के विचारों पर खुलकर विचार करने की अपील की। मंच ने कहा कि उनके विचार किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने और भारत को मजबूत बनाने के लिए हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर मंच ने गहरी चिंता व्यक्त की। मंच ने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वह हिंदू, बौद्ध, और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। संभल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मंच ने मुसलमानों से राजनीतिक दलों के षड्यंत्रों से बचने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

प्रधानमंत्री क्रिसमस समारोह में पहुंचे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में पहुंचे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जर्मनी के क्रिसमस बाजार में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश होती है तो उन्हें दुख होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर, यह दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है।

परभणी पहुंचे राहुल गांधी, सोमनाथ के परिवार से मिले

नइदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की, जिनकी इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के परभणी शहर में हिंसा के बाद न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। राहुल ने कहा कि मैं उनके परिवार और उन लोगों से मिला हूं जो मारे गए और पीटे गए। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने दावा किया कि यह 100 फीसदी हिरासत में मौत है। उनकी हत्या हुई है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला।

राहुल ने आगे कहा कि उनके जवान को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस की विचारधारा संविधान को नष्ट करने

की है। हम चाहते हैं कि यह मामला तुरंत सुलझे और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें सजा मिले। कोई राजनीति नहीं की जा रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि विचारधारा जिम्मेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है इसलिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उन्हें मारा है वे जिम्मेदार हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।

परभणी में 10 दिसंबर की शाम को मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बंद प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा देखी गई। परभणी के शंकर नगर निवासी सूर्यवंशी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 50 से अधिक लोगों में शामिल थे।

उनका काम नफरत फैलाना-फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने राहुल पर अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां सिर्फ राजनीतिक मकसद से आए हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक बैठक थी, लोगों के बीच जातिगत आधार पर नफरत पैदा करने की कोशिश है, वो ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका काम नफरत फैलाना है।

प्रमुख समाचार

अंबेडकर को लेकर नाटक कर रही है कांग्रेस-रविशंकर

नईदिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका हौ लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थम नाम रहा है। कांग्रेस

समेत पूरा विपक्ष भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। इन सबके बीत पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी देशभर में कुछ नाटक कर रही है। अंबेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं। रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉ भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉ भीमराव अंबेडकर को 1952 लोकसभा चुनाव में हरवाया फिर 1954 के उप-चुनाव में हरवाया। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉ भीमराव अंबेडकर को मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दें। जिस कांग्रेस ने डॉ भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया। उन्हें 1989 में भारत रत्न देने का काम भाजपा समर्थित सरकार ने किया।

आठ जनवरी को एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव पर होगी चर्चा

नईदिल्ली। एक देश-एक चुनाव पर 39-सदस्सीय संसदीय समिति की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी। इस बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। संसदीय सूत्रों ने यह

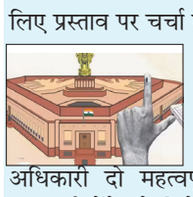

जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह प्रारंभिक जानकारी देने वाली बैठक होगी। इस बैठक में अधिकारी दो महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे। ये विधेयक हैं- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए जरूरी बदलाव करना है। यह कदम भाजपा द्वारा लंबे समय से किए जा रहे वादे का हिस्सा है। पिछले हफ्ते इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को इन्हें संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इस समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 की गई है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी। भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को आजीवन मिलेगा वेतन

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में आचार्य सत्येंद्र दास 34 वर्षों से मुख्य पुजारी का जिम्मा संभाल रहे हैं। ट्रस्ट ने उन्हें आजीवन वेतन देते रहने का निर्णय लिया है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने सत्येंद्र दास की बढ़ती उम्र एवं खराब स्वास्थ्य के चलते उनसे कार्य से मुक्ति का निवेदन भी किया है। ट्रस्ट ने कहा कि मुख्य पुजारी पहले की तरह जब भी चाहेंगे, उनके राममंदिर में आने-जाने व पूजा-अर्चना करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। पिछले 25 नवंबर को हुई रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय हुआ कि राममंदिर में पिछले 34 सालों से सेवा दे रहे आचार्य सत्येंद्र से कार्य से मुक्ति का निवेदन किया जाए। सत्येंद्र दास 87 साल के हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य भी अब अनुकूल नहीं रहता, इसलिए उनसे सेवा से मुक्ति का निवेदन किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय हुआ कि अभी उन्हें जो पारिश्रमिक यानी वेतन दिया जा रहा है, वह वेतन आजीवन दिया जाएगा। इस पर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की सहमति भी मिल गई। आचार्य सत्येंद्र दास 1 मार्च 1992 से राममंदिर में मुख्य अर्चक के रूप में सेवा दे रहे हैं। शुरुआत में उन्हें 100 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका वेतन बढ़कर 38500 रुपये हो गया है।

राज्य अब कक्षा 5वीं और 8वीं में छात्रों को कर सकेंगे फेल

नईदिल्ली। स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अपने द्वारा शासित स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है, जो उन छात्रों को फेल करने की अनुमति देती है जो साल के अंत की परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दोनों कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। एक गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे दो महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा।

यूपी-पंजाब पुलिस से मुठभेड़ में तीन खालिस्तानी आतंकी ढेर

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में यूपी और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में तीन खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आतंकी संगठन के थे। मौके से दो एके-47 और दो पिस्टल बरामद की गई हैं। तीनों ने गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। पूरनपुर क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर के करीब सोमवार सुबह करीब पांच बजे मुठभेड़ हुई। ये आतंकी मारे गए, गुरविंदर सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह (25 वर्ष) निवासी मोहल्ला कलानौर, थाना कलानौर जिला गुरदासपुर, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र रंजीत सिंह उर्फ जीता (23 वर्ष) निवासी ग्राम अगवान थाना कलानौर जिला गुरदासपुर, पंजाब, जसन प्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह (18 वर्ष) निवासी ग्राम निक्का सूर, थाना कलानौर जिला गुरदासपुर, पंजाब।

पाकिस्तान की राह पर नेपालः भारत की सतर्कता अहम

केएस तोमर

चीन के प्रति झुकाव रखने वाले घोर कम्युनिस्ट नेता नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश को चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) परियोजना से जोड़ लिया है। नेपाल के विकास आख्यान में 'टर्निंग पॉइंट' के रूप में इस निर्णय को लेकर काठमांडो में जश्न मनाया गया, जिससे भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों में दरार पड़ने का खतरा है, क्योंकि भारत ने शुरू से ही बीआरआई के जोखिम भरे ढांचे का विरोध किया है।

प्रधानमंत्री के रूप में ओली के पिछले कार्यकाल में नेपाल के विवादास्पद नक्शे में भारतीय क्षेत्रों लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल किया गया था, जिसे भारत ने सख्ती के साथ खारिज कर दिया था।

हैरानी की बात यह है कि नेपाल की गठबंधन सरकार में नेपाली कांग्रेस (भारत समर्थक) का वर्चस्व है। इसके बाद भी ओली ने बीआरआई के बारे में आम सहमति लेने की जहमत नहीं उठाई है, जो भविष्य में हिमालयी देश में राजनीतिक गतिशीलता पर असर डाल सकता है। इससे पहले 13 जुलाई, 2020 को नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती समारोह के दौरान ओली ने यह दावा कर विवाद खड़ा किया था कि भगवान राम से जुड़ा ऐतिहासिक राज्य अयोध्या भारत में नहीं, बल्कि नेपाल में बीरगंज के पश्चिम में स्थित है।

ओली ने छेड़ दी थी बहस

ओली की टिप्पणियों ने भारत और नेपाल में संवेदनशील सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को छूते हुए एक बहस छेड़ दी। वहीं ओली की टिप्पणियों को कुछ लोग राजनीतिक नजरिये से, तो कुछ नेपाल की विरासत के दावे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बीआरआई के बारे में प्रधानमंत्री का निर्णय बड़ा दांव साबित होगा,

जो नेपाल की भू-राजनीतिक पहचान को पुनर्परिभाषित कर सकता है। नेपाल ने बीआरआई को अपनाकर अपने तटस्थ रुख से हटकर भारत और अमेरिका से टकराव लेने के संकेत दिए हैं।

नेपाल का यह बदलाव पड़ोसी और वैश्विक शक्तियों के हितों के बीच कुशल कूटनीति को संदर्भित करने की मांग करता है। ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वादा करते हुए इस पहल में आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक उलझनों के खासे जोखिम हैं। चीन की 'ऋण जाल कूटनीति' ने कई देशों को अपने जाल में फांस लिया है। विशेष रूप से पाकिस्तान को, जिस पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत अनुमानित 25 अरब डॉलर का बकाया है।

लगभग 38 अरब डॉलर के कर्ज के बोझ तले नेपाल पहले से ही दबा है। चीन ने नेपाल को तीन अरब डॉलर का नया ऋण दिया है, जिसमें जलविद्युत, सड़क निर्माण और हवाई अड्डा परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है, जबकि उसके ऊपर भारत का ऋण 1.5 अरब डॉलर है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान और ऋण पर जोर दिया गया है।

ओली का बीआरआई को समर्थन भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को भी चुनौती देता है। नई दिल्ली का बीआरआई को लेकर विरोध उसकी संप्रभुता संबंधी चिंताओं को लेकर है, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संबंध में, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है।

चीन की पहल की ओर नेपाल का झुकाव भारत की क्षेत्रीय पहल, जैसे बीबीआईएन (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) ढांचे को कमजोर करता है। ओली का निर्णय एक तरह से नेपाल की विदेश नीति में बदलाव को दर्शाता है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत से पहले उनकी चीन यात्रा इस ओर इशारा कर ही रही थी। अब बीआरआई को औपचारिक रूप से अपनाने से नेपाल भारत से दूर हो गया है और भारत-नेपाल संबंधों में ऐतिहासिक संतुलन को चुनौती मिली है।

ओली के बीआरआई निर्णय का घरेलू राजनीति पर भी असर होगा। परंपरागत रूप से भारत की करीबी नेपाली कांग्रेस ने ऋण जोखिम और रणनीतिक कमजोरियों का हवाला देते हुए इस पहल का विरोध किया है। यह कलह ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ाने के साथ ही गठबंधन सरकार को अस्थिर कर सकता है।

इसके अलावा, नेपाल के हुम्ला जिले में चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट, जहां सीमा पर निगरानी टावर और कांटेदार तार की बाड़ दिखाई दी है, ने स्थानीय विरोध को जन्म दिया है। इन उकसावों पर ओली की चुप्पी बीजिंग के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है, जिससे उनके नेतृत्व में नेपाल की संप्रभुता पर भी सवाल उठते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन की रणनीतिक हठधर्मिता उसके आर्थिक और बुनियादी ढांचे में स्पष्ट है। अनुदान के बजाय ऋण को बीजिंग की प्राथमिकता ने कई देशों में निर्भरता का एक चक्र बना दिया है। पाकिस्तान का सीपीईसी ऋण बढ़कर 62 अरब डॉलर हो गया है, जो चीन की चाल को स्पष्ट करता है। नेपाल भी उसी रास्ते पर चलने का जोखिम उठा रहा है।

नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश, जवानों ने बरामद किया 15 जिंदा आईईडी

■ नारायणपुर में डीआरजी और बीएसएफ टीम को बड़ी सफलता

नारायणपुर। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जवानों की टीम जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में रविवार को नारायणपुर में डीआरजी और बीएसएफ की टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान जवानों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने जंगलों, पहाड़ों और अलग अलग रास्ते में नक्सलियों के प्लांट किए 15 आईईडी बरामद किए। सभी आईईडी 5-5 किलो के थे।

नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि नक्सल विरोधी सर्चिंग अभियान के लिए नए कैंप कच्चापाल से डीआरजी और बीएसएफ 153 वीं वाहिनी की संयुक्त टीम को तोके और मुसेर की ओर रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान कच्चापाल और तोके के बीच पहाड़ियों में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से 15 आईईडी लगाए गए थे। जवानों ने आईईडी रिकवर किया और बीडीएस टीम को बुलाया। बीडीएस की टीम ने सभी जिंदा आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। नष्टीकरण के बाद अवशेष व बिजली वायर को बरामद किया गया।

एसपी ने बताया कि 3 दिन पहले इसी जंगल में आईईडी विस्फोटक हुआ था। जिसमें डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए थे। एसपी

ने बताया कि 2024 में अब तक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 30 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो चुके हैं। 2 दिन पहले अबूझमाड़ में एक मादा भालू व उनके बच्चों की मौत हुई थी।

नक्सलियों ने बीजापुर में जन अदालत लगाकर दो ग्रामीणों की हत्या की

बीजापुर। जिले में नक्सली आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर दो आदिवासी ग्रामीणों की जनअदालत लगाकर हत्या कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गंगालुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरचोली में शनिवार को नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर आदिवासी युवक कमलू पोटाम व एक अन्य आदिवासी ग्रामीण की हत्या कर दी है।

इस हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की खबर परिजनों ने नक्सलियों के भय से पुलिस को नहीं दी है। जानकारी मिली है कि परिजनों ने रविवार को ही मृतकों के अंतिम संस्कार भी कर दिए थे।

जेसीसीजे कार्यकर्ता को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट

बीजापुर। बीजापुर में बीते दिनों रेड्डी के साप्ताहिक बाजार से अगवा किये जेसीसीजे के कार्यकर्ता की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। नक्सलियों ने शव के पास पर्चा भी छोड़ा है।

जानकारी के मुताबिक बीते दिनों गंगालुर थाना क्षेत्र के ग्राम रेड्डी के साप्ताहिक बाजार से नक्सलियों ने जेसीसीजे कार्यकर्ता मुकेश हेमला को पिस्तौल की नोक पर उठा ले गये थे। नक्सली जब मुकेश को ले जा रहे थे, उस वक्त वहां के कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन नक्सलियों ने उन्हें पिस्तौल व चाकू दिखाकर धमका दिये और वहां से वापस चले जाने को कहा। नक्सली मुकेश को अपने साथ ले गए।

नक्सलियों ने अपहृत मुकेश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया। नक्सलियों ने शव के पास एक पर्चा भी छोड़ा है। ज्ञात हो कि गंगालुर इलाके में तीन दिनों में तीन लोगों की हत्या कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की है।

नक्सलियों ने अपने ही साथी को उतारा मौत के घाट

दंतेवाड़ा। बस्तर में नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। हालांकि अब तक मामले की अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से परिजन दहशत में है। परिजनों ने कोई एफआईआर भी नहीं करवाई है। यह मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है।

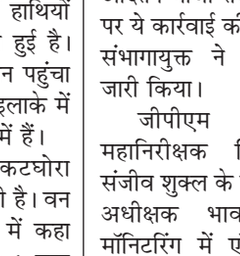

जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों ने गुफापारा में सामनाथ कश्यप की हत्या की है। घटना को अंजाम देने दर्जनभर हथियारबंद नक्सली पहुंचे थे। सामनाथ नक्सलियों के संगठन में लंबे समय से जुड़ा हुआ था। नक्सली कमेटी में जनताना सरकार का अध्यक्ष था।

नक्सलियों के स्पाइक होल में गिरकर डीआरजी जवान घायल

बीजापुर। दंतेवाड़ा और बीजापुर के जवान रविवार को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पुन्नूर के पास जंगल में जवान स्पाइक होल में गिर गया। जवान को चोट आई है।

घायल जवान का नाम आशीष नाग है। जो दंतेवाड़ा डीआरजी में पदस्थ हैं। दो जिले के कई जवान नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए निकले थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान डीआरजी जवान नक्सलियों के लगाए स्पाइक होल की चपेट में आकर जख्मी हो गया। जिसके बाद साथी जवान उसे जिला हॉस्पिटल लेकर गए। जहां जवान का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जवान को हल्की चोट आई है।

स्पाइक होल क्या है: नक्सल प्रभावित बस्तर में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली स्पाइक होल का इस्तेमाल करते हैं। जंगल, पगडंडियों और रास्तों में छोटे और बड़े गड्ढे खोदकर उनमें नुकीले लोहे के रॉड, नुकीले कांच, नुकीले पत्थर और बांस को छीलकर उसमें रख दिया जाता है। उस गड्ढे को ऊपर से पत्ते और मिट्टी से ढक दिया जाता है। सर्चिंग के दौरान जवान उन गड्ढों को भांप नहीं पाते और उसमें फंसकर जवान गिर जाते हैं।

स्पाइक होल से ना सिर्फ जवानों को गहरी चोट पहुंचती है बल्कि जवानों पर हमला करने के लिए भी नक्सली इस ट्रैप का यूज कर करते हैं। नक्सलियों के स्पाइक होल्स से आम लोगों के साथ मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचता है।

धान खरीदी केंद्र पर मंडराया हाथियों का खतरा

देसी जुगाड़ से धान बचा रहे कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर हाथी भगा रहे हैं

कोरबा। कोरबा के करतला में धान उपार्जन केंद्र पर हाथियों का खतरा मंडरा रहा है। करतला विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र नवापारा के आसपास 22 हाथियों का दल घूम रहा है। समिति के कर्मचारी रातगजा करके हाथियों को धान खरीदी केंद्र से दूर खदेड़ने की कोशिश में लगे हैं।समिति में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो वनविभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। वो खुद ही देसी तरीकों से हाथी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

नवापारा धान खरीदी केंद्र की क्षमता 90 हजार क्विंटल है। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद यहां बड़ी मात्रा में धान रखा हुआ है। धान हाथियों का पसंदीदा भोजन भी होता है। जंगल में खाना नहीं मिलने पर वह हाथी धान की खुशबू से आकर्षित होते हैं। धान खरीदी शुरू होने के कुछ दिन के बाद से ही हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। रात होते ही वह उपार्जन केंद्र के समीप पहुंच जाते हैं।

नवापारा में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने हाथियों को खदेड़ने का देसी जुगाड़ वाला तरीका इजाद किया है। समिति के प्रबंधक जबल सिंह राठिया का कहना है कि किसानों से उधार लिए ट्रैक्टर के जरिए

रात भर हाथी को खदेड़कर धान की सुरक्षा कर रहे हैं।

समिति प्रबंधक जबल सिंह राठिया ने कहा केंद्र के आसपास 22 हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया। शाम ढलते ही हाथियों का दल मंडी में घुसने की कोशिश करता है। उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फड़ के कर्मचारी ट्रैक्टर के जरिए हाथी को खदेड़ रहे हैं। कई लीटर डीजल भी इसमें खर्च हो जाता है। वन विभाग के कर्मचारी एक बार यहां आए थे, लेकिन उसके बाद हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम खुद ही हाथियों को धान से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं।

पिछले 15 दिनों से यहां हाथियों का तांडव जारी है। रात के समय चौकीदारी का काम करने वाले पदी राम कहते हैं कि रात के समय हमें ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हाथी लगातार खरीदी केंद्र में घुसने का प्रयास करते हैं। हम ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल कर तेज आवाज करके किसी तरह हाथियों को यहां से दूर रखने की कोशिश करते हैं।

चौकीदार पदीराम ने कहा हाथी केंद्र के एकदम पास आ जाते हैं। वन विभाग के कर्मचारी कहते हैं की खरीदी केंद्र के अंदर मत जाओ, हाथियों के करीब मत जाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो हाथी पूरा धान चट कर जाएंगे, पिछले 15 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। हम लगातार परेशान हैं।

करतला और कुदमुरा रेंज में 30 से अधिक हाथी अलगङ्कअलग दल में विचरण कर रहे है। कुछ दिन पहले एक हाथी चचिया के धान उपार्जन केंद्र में घुस गया था। इसके बाद हाथियों का एक दल नवापारा मंडी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। इन्हें खदेड़ने में वन अमला नाकाम रहा है, जबकि समिति के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर अपनी और धान की सुरक्षा कर रहे हैं। नवापारा के साथ ही चचिया, बोतली जैसे गांव में हाथी बने हुए हैं। इस क्षेत्र में रेल लाइन और भारतमाला प्रोजेक्ट के हाइवे का भी काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है। जंगल का दायरा सिमटा है। इसके कारण भी हाथी लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ प्रवेश कर रहे हैं।

चैतमा में टाइगर की दहाड़, कटघोरा वन मंडल के कई इलाकों में अलर्ट

इन दिनों जिले के जंगलों में हाथियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी बनी हुई है। हाथी धान और मकान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बीच जिले के सरहदी इलाके में बाघ की दहाड़ से ग्रामीण दहशत में हैं।

कोरबा वन विभाग ने कटघोरा वनमंडल में बाघ घूमने की पुष्टि की है। वन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मरवाही वनमंडल से 1 बाघ घूमते हुए कटघोरा फॉरेस्ट रीजन के पसान जंगल में पहुंचा है। निर्देश में ये भी कहा गया है कि सब रेंजर, रेंज असिस्टेंट, कैंपस गार्ड अपने अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें। ये भी कहा गया है कि जंगल से लगे सभी ग्राम पंचायतों के गांव में बाघ दिखने की मुनादी कराते हुए गांव वालों को सतर्क रहने का वीडियो बनाकर इसे ग्रुप में शेयर करने को भी कहा गया है।

जीपीएम में पहली बार आदतन गांजा तस्कर पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

गांजा तस्कर पर गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में गांजा तस्करी के आरोपी पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम पीआईटी एनपीडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में पहली बार आदतन गांजा तस्करी के आरोपी पर ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर संभागायुक्त ने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया।

जीपीएम में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज संजीव शुक्ल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की मॉनिटरिंग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पीआईटी एनपीडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके तहत गौरेला थाना क्षेत्र के रानीझाप में रहने वाले 43 वर्ष के रमेश राठौर पर प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार संलिप्तता के आरोप पर सुनवाई करते हुए डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया।

बिलासपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने सुनवाई के बाद डिटेंशन वारंट जारी कर रमेश को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रमेश राठौर पर इससे पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के कई आरोप दर्ज किए गए। साल 2021 में 1505 किलो गांजा की तस्करी के दौरान भी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। जमानत के बाद उसने दोबारा गांजा तस्करी शुरू कर दी। डिटेंशन ऑर्डर जारी होते ही रमेश राठौर को गौरेला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की अवैध संपत्तियों की गहन जांच की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दूसरे नेटवर्क की जांच पड़ताल भी जारी है।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया यह कार्रवाई समाज को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। आदतन अपराधियों को सख्त संदेश देने के लिए यह जरूरी था। इस तरह की कार्रवाई पुलिस आगे भी करेगी।

पीआईटी एनपीडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल रहते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा में बाघ के बाद मगरमच्छ आया, गांव में फैली सनसनी

कोरबा। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में अलग-अलग प्रकार के जंगली जानवरों की आमदगी लगातार बनी हुई है। पाली रेंज के चेतमा इलाके में जहां पहले बाघ देखे जाने की खबर सामने आई थी। वहीं अब इसी क्षेत्र के शिवपुर में मगरमच्छ के मिलने से सनसनी फैल गई। मगरमच्छ शिवपुर के तालाब से निकलकर सड़क पर आ गया। जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर वन विभाग को सूचना दी गई। कोरबा के पड़ोसी जीपीएम जिले से जंगली जानवर लगातार कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कटघोरा वन मंडल के चैतमा जंगल में बाघ को देखे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। वन विभाग के साथ ही ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि बाघ ने किसी मवेशी का शिकार भी किया। वहीं अब पाली के शिवपुर में मगरमच्छ मिला है। बताया जा रहा है,कि मगरमच्छ गांव के तालाब से निकलकर सड़क पर आ गया था। जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

पूर्व एल्डरमैन से 50 हजार रु. की लूट, एक आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर-चांपा जिले की सारागांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम कोसमंदा-कमरीद मुख्य मार्ग पर हुई लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी अनुसार दिनांक 15 दिसंबर 2024 को प्रार्थी केशव करियारे निवासी सारागांव मोटरसाइकिल से कोटाडबरी से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 8:30 बजे ग्राम कमरीद के पास तीन अज्ञात आरोपियों ने उनका रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की, और बैग में रखे रू. 50,000 लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में मामला दर्ज किया गया।पुलिस को मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक कुमार उर्फ पिंटू कश्यप (24 वर्ष), निवासी गौद, थाना जांजगीर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि रू. 50,000 में से उसे रू. 15,000 का हिस्सा मिला, जिसमें से रू.12,000 खर्च कर दिए और ?3,000 शेष बचा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया।

छतौना मोड़ के पास चलती स्कूटी में अचानक लगी आग

बिलासपुर। शनिवार शाम हाईकोर्ट रोड स्थित छतौना मोड़ के पास चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। एक युवक और दो बच्चे स्कूटी में सवार थे जो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। युवक और दो बच्चे सुरजीत ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास स्कूटी से जा रहे थे, तभी स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही देखते आग में तब्दील हो गया और स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। आग बूझने के बाद स्कूटी की पहचान भी मुश्किल हो गई, केवल हेडलाइट बची रही, जबकि बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस बीच, पीछे आ रही एक कार के चालक ने स्कूटी पर सवार युवक को आग की जानकारी दी। जैसे ही युवक को इसकी जानकारी मिली, उसने तुरंत गाड़ी रोकी और दोनों बच्चों के साथ स्कूटी से उतरकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। शुक्र है कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

जेडआरयूसीसी में विधायक सुशांत शुक्ला सदस्य नामित

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी) में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह समिति रेलवे उपयोगकर्ताओं और रेल प्रशासन के बीच परामर्श और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कार्य करती है। भारतीय रेल द्वारा इस समिति का गठन रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने, उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए किया जाता है। इस समिति के सदस्य समय-समय पर रेल सुविधाओं और सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को रेल प्रशासन के समक्ष रखते हैं। विधायक शुक्ला ने कहा कि वे पहले से ही रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हैं और अब जेडआरयूसीसी में सदस्य बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे अपने क्षेत्र के रेलवे उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को उठाने और सेवाओं में सुधार के लिए प्रयासरत रहेंगे।

पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में तस्करों को पकड़ा

जशपुर। फिल्मी स्टाइल में जशपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते चार लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्कर ट्रक में मवेशियों को भरकर झारखंड के कत्लखाना ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक के सामने नुकीली ब्रेकर डालकर गाड़ी को रोका। ट्रक का टायर फटने के बावजूद मवेशी तस्कर गाड़ी चलाते रहे। इस दौरान डिक्स में ट्रक चलाने से गाड़ी में भीषण आग लग गई। फिर तस्कर जान बचाने गाड़ी से कूदे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। ट्रक में 18 मवेशी थे। पुलिस ने आग लगने के बाद सुरक्षित 14 मवेशियों को ट्रक से उतारा। इनमें से 6 मवेशियों की मौत ट्रक में दम घुटने से हो गई। वहीं पुलिस ने 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी झारखंड के रहने वाले हैं। यह कार्रवाई पुलिस लाइन में पदस्थ टीआई हर्षवर्धन चौरासे और उसकी टीम ने कार्रवाई की।

बच्चों की ट्यूशन फीस सहित जरूरी खर्चों में उपयोग होता है मिली राशि का : मीना

■ महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सुखद सहारा

कांकेर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में न सिर्फ अपार खुशियां लेकर आई है, बल्कि एक सुखद सहारा सिद्ध हो रही है। कांकेर शहर के इमलीपारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती मीना देवांगन को उक्त योजना के तहत प्रति हजार प्रति माह के मान से अब तक 10 किश्तों में कुल 10 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। ये पैसे मीना के लिए केवल एक आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं।

श्रीमती मीना ने बताया कि वह इन पैसों का उपयोग बड़ी सूझबूझ से करती हैं। अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भरने से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों में खर्च करने तक, उन्होंने इन पैसों का

सदुपयोग किया है। साथ ही, वह इन पैसों से सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश करती हैं, ताकि अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित कर सकें।

श्रीमती मीना ने बताया कि वह घर पर सिलाई का काम भी करती हैं और अपनी मेहनत से घर चलाने में आवश्यक सहयोग करती हैं। महतारी वंदन योजना से मिले पैसे ने उन्हें सिलाई के काम में भी मदद की है। इस योजना ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है। वह कहती हैं- प्रदेश सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। इस योजना ने हमें एक नई दिशा दी है। इसके लिए हम सरकार का दिल से धन्यवाद करते हैं।

छत्तीसगढ़ में पांच दिन संत समागम, बेमेतरा में खाद्य मंत्री ने लिया जायजा

■ 31 दिसंबर से जुटेंगे लाखों कबीरपंथी

बेमेतरा। जिला मुख्यालय बेमेतरा से पांच किमी दूर लोलेसरा गांव में कबीरपंथ के वंश गुरु पंथ श्री उग्रनाम साहेब की स्मृति में संत समागम समारोह का आयोजन किया जाना है। कबीर पंथ से जुड़े इस महत्वपूर्ण स्थल लोलेसरा में 31 दिसंबर से चार जनवरी तक चार दिवसीय संत समागम मेले का आयोजन होगा। इस मेले में देशभर से लाखों की संख्या में कबीरपंथी शामिल होते है।

संत समागम समारोह के आयोजन की तैयारी लेकर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक व खाद्य मंत्री दलायदास बघेल ने मौके का निरीक्षण किया। मंत्री ने मेला स्थल निरीक्षण के दौरान पेयजल, प्रकाश, पार्किंग और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था के लिए निर्देश

दिए।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि मेला स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे सुरक्षा, स्वच्छता, पानी और भोजन की व्यवस्था, समय पर उपलब्ध हो। मेले में आने वाले श्रद्धालु व संतों के लिए विशेष इंतजाम करने कहा है, ताकि आयोजन सफल और सुरक्षित हो। मेले के दौरान पुलिस-प्रशासन उचित व्यवस्था कर लें। मेला स्थल में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहें,ताकि चोरी जैसी घटनाएं न हो। कबीरपंथ के पदाधिकारियों से कहा कि चार दिवसीय मेला अंतर्गत अलग-अलग दिन के लिए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। मेला समिति के अध्यक्ष विजेन्द्र वर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई।

इस मौके पर बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मेले की तैयारी को लेकर सभी संबंधित अधिकारी को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।मेले के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहने व सभी व्यवस्था की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया, ताकि आयोजन सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने मेले के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने मेले में पुलिस की तैनाती को लेकर विशेष ध्यान देने को कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधित समस्या न हो। एसपी ने मेले में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी शामिल है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, एसडीएम दिव्या पोटाई उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर डेडलाइन तय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी जिला कलेक्टरों को एक हफ्ते के भीतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर जानकारी प्रषित करने के आदेश दिए हैं। बता दें, बीते दिनों आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद आज आरक्षण प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के बाद जल्द ही पंचायत चुनाव होने की संभावना है।

कैफे में लगी आग, ऊपर अस्पताल में मचा हड़कंप

रायपुर। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव, तेलीबांधा के सामने स्थित एक कैफे में सोमवार सुबह आग लग गई। सिप एंड बाइट कैफे में आग लगने से धुंआ बाहर आने लगा। जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायरब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, तेलीबांधा तालाब के सामने सिप एंड कैफे में सोमवार सुबह आग लग गई। कैफे से बाहर आ रहे धुंए को देखने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस और दमकल की एक वाहन भी पहुंच गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की वाहन आग बुझाने में जुटी हुई है। दुकान के ऊपर अस्पताल है, आग लगने से हड़कंप मच गया है।

डॉ. कुलदीप सोलंकी बने आईएमए के नए अध्यक्ष

रायपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। डॉ. कुलदीप सोलंकी 121 वोट से जीतकर आईएमए के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्हे 322 वोट मिले। वहीं एकता पैनल से अध्यक्ष पद की दावेदार डॉ. आशा जैन को 201 वोट मिले। अन्य विजयी प्रत्याशियों में उपाध्यक्ष द्वय डॉ. केतन शाह, डॉ. किशोर और सचिव डॉ. संजीव श्रीवास्तव चुने गए। बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया रविवार को रोटरी मैत्री भवन जलविहार कॉलोनी में संपन्न हुई। 65 प्रतिशत मतदान हुआ। 800 में से 525 डाक्टरों ने मतदान किया। उपाध्यक्ष पद पर डाक्टर किशोर झा और डाक्टर केतन शाह निर्वाचित घोषित किए गए। डा.झा को 308 और शाह को 384 वोट मिले। इसी प्रकार डा.संजीव श्रीवास्तव 292 वोट पाकर महासचिव निर्वाचित हुए। एक पैनल की कमान डॉ. विमल चोपड़ा और दूसरे पैनल की डॉ. राकेश गुप्ता ने संभाल रखा था।

साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे जागरुकता कैंप

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंघोत्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज की एक आवश्यक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सिक्ख समाज के सभी जरूरतमंद युवक -यूतियों, बच्चों - बुजुर्गों सहित जरूरतमंद परिवारों को जिन्हें जिस तरह की भी सहायता की आवश्यकता है वह छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज से संपर्क करें । छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज जरूरतमंद सभी सिक्खों की आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करेगा, उन्हें पग - पग पर हर तरह की मदद करेगा, समाज के युवक - युवतियों सहित परिवारों को स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यापार, नौकरी के साथ-साथ कानूनी हेल्प भी करेगा। बच्चों को सिक्ख इतिहास, गुरुओं के बलिदान की भी जानकारी देकर देश धर्म सहित देश प्रेम के प्रति जागरूक करेगा। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने प्रदेश के सभी जरूरतमंद परिवारों से आग्रह किया है कि उनके दुख परेशानियों और बच्चों के भविष्य के लिए समाज हमेशा तत्पर रहेगा, किसी भी परेशानी, आवश्यकता के लिए जरूरतमंद 9301094242-Email : sukhbir94242@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ईसाई धर्म का प्रचार करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में 6 गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के

शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में धर्मांतरण करने की कोशिश के मामले में दो पुरुष और चार महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपियों के पास से इसाई धर्म के कुछ पर्चे बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना के रहने वाले हैं। दरअसल शनिवार को आवेदक बुद्धेश्वर केशरवानी ने शिवरीनारायण थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि वह अपने उत्सव इलेक्ट्रिकल्स दुकान में बैठा हुआ था। इस दौरान दोपहर करीबन 12.15 बजे कुछ महिलाएं और पुरुष आकर एक पुस्तक दिया जिसमें लिखा था उपहार जो सब कुछ बदल देता है कहने लगे हमारे प्रभु यीशु मसीही का उपहार है आप सभी ईसाई धर्म को अपना लें प्रभु यीशु मसीह अधिक शक्तिशाली हैं और दैविक शक्ति से परिपूर्ण हैं, हिंदू धर्म को छोड़ दें। वहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपशब्द कहते हुए अपमानित किया गया। जिससे हिन्दू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। शिवरीनारायण थाने में अपराध दर्ज कर संजय साहू 33, कृष्णा साहू 33, गायत्री साहू 28, पुनीबाई साहू 35 , सुशीला साहू 35, गिरजा साहू 38 निवासी गोधना को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नक्सली इमारत का जमींदोज होना नक्सलवाद के खात्मे का बिगुल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के कोमटपल्ली गाँव में सोमवार को नक्सलियों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े नक्सली स्मारक को धराशायी करने और 25 लाख रु. के इनामी हार्डकोर नक्सली प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव की गिरफ्तारी की पुष्टि किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह नक्सल क्षेत्र में मिली एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री रोहरा ने कहा कि स्मारक को धराशायी करना और हार्डकोर नक्सली को धर दबोचना, दोनों ही छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें अब उखड़ रही हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री रोहरा ने !केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों के खूनी खेल का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जिस तरह केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ समन्वित रणनीति बनाकर काम कर रही है, उससे उम्मीद की वह मशाल धधकने लगी है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देश और छत्तीसगढ़ को दिए गए भरोसे से प्रज्जवलित हुई है कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद को लेकर जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि यह अब निर्णायक लड़ाई पर आ चुका है। फोर्स अब पूरी ताकत से माओवादी संगठन को कुचलने का काम कर रही है, जिसमें उन्हें लगातार सफलता भी मिल रही है। श्री रोहरा ने कहा कि इस वर्ष फोर्स ने केवल छत्तीसगढ़ में ही सवा 2 सौ से अधिक माओवादियों को ढेर किया है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री रोहरा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक विजन के साथ नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के लिए सख्त फैसले लिए हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और पुलिस के जवान माओवाद पर निर्णायक प्रहार कर रहे हैं।

जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अद्भुत माध्यम है जनसंपर्क : साव

■ पीआरएसआई के नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव पीआरएसआई के 46वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस-2024 के समापन में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। उन्होंने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि पीआरएसआई ने अपने 46वें अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। मैं देशभर से आए प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि और माता कौशल्या की इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ पर असीम कृपा बरसाई है। छत्तीसगढ़ ऐसा भू-भाग है जिसका उल्लेख हर काल में मिलता है। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, पौराणिक एवं प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध रहा है। यहां एक ओर पहाड़, जंगल और नदियां हैं, तो दूसरी ओर कोयले से लेकर हीरे तक के भंडार हैं। यही छत्तीसगढ़ की ताकत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जितना विकास और विश्व पटल पर नाम होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। देशभर के लोग आज यहां आए हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विशेषताएं देशभर में जाएंगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जनसंपर्क की ताकत संचार कौशल में है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जनसंपर्क अद्भुत माध्यम है, जिसमें लगातार इनोवेशन हो रहे हैं। इन इनोवेशन्स के कारण जनसंपर्क की क्षमता का विस्तार भी हो रहा है। तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के दर्शन के साथ हुआ। सम्मेलन में जनसंपर्क के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया।

तोखन साहू ने रोजगार मेले में प्रदेश के 450 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र

आरंग। केंद्र सरकार के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअली 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा. आरंग के ग्राम भिलाई स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय राज्य मंत्री (आवास एवं शहरी) तोखन साहू ने 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू, सीआरपीएफ अपर महानिदेशक अमित कुमार,डीआईजी अजय सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मेले का आयोजन होता था, जिसमें लोग मेले का आनंद लेते थे।

लेकिन देश में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने है तब से देश में रोजगार मेला, आवास मेला, किसान मेला जैसे कई योजनाओं के लिए मेला का आयोजन किया जा रहा है। मोदी की गारंटी के तहत पूरे देश में विकास कार्य हो रहे है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को समर्थन मूल्य पर फसलों की कीमत मिल रही है। साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और इस संकल्प को पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता है।

उन्होंने प्रदेश में भाजपा सरकार के एक साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को 10 में से पूरे 10 अंक दिए है। उहोंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खुशहाली है। किसानो से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद कर 3100 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है।

अपराधियों की अब खैर नहीं पुलिस ने चलाया अभियान

खैरागढ़। शहर में अपराधों पर लगाम लगाने खैरागढ़ पुलिस ने आधी रात अभियान चलाया। जिससे पुलिस ने अपराधियों को अपराध करने पर कड़ी कार्रवाई करने का सीधा सन्देश दिया। पुलिस ने आधी रात से लेकर तड़के 4 बजे तक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 26 बदमाशों के घरों में जाकर कड़ी चेतवानी दी गई। अपराधियों से साफ शब्दों में कहा गया, अपराध से तौबा करो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। गली-मोहल्लों के साथ गस्त के दौरान पुलिस ने बैंकों, एटीएम, सर्राफा दुकानों और आउटर बायपास रोड पर पैनी नजर बनाकर रखी। साथ ही देर रात सड़कों पर घूमने वाले, संदिग्धों और नशेबाजों से पूछताछ और जांच की गई। इन बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराकर चेतवानी दी गई। पुलिस ने इस अभियान से आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी जगाई गई है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल शर्मा की अगुवाई में अभियान चलाया गया। जिसमें ओपी जालबांधा और रक्षित केंद्र के जवान शामिल रहे। पुलिस ने अपराधियों को अपराध नहीं करने का कड़ा सन्देश दिया, साथ ही जनता को भरोसा दिलाने का काम किया।

18 जिलों के 310 तीरंदाजों में 18 बने विजेता

रायपुर। साइंस कालेज मैदान के तीरंदाजी अकादमी ग्राउंड में रविवार को एक दिवसीय सब जूनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 18 जिले से 310 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर व पदाधिकारी शामिल हुए। जिसमें 18 तीरंदाज विजेता बने। इस प्रतियोगिता में पैरा आर्चरी के 15 तीरंदाज भी शामिल हुए। इस अवसर पर वनवासी विकास समिति के संगठन मंत्री रामनाथ कश्यप, वनवासी का समिति के प्रदेश महामंत्री अनुराग जैन और बालोद जिला के तीरंदाजी के प्रमुख लुनिया, छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका ने विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत किया।

मुख्य अतिथि रामनाथ कश्यप ने कहा कि वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले चाहे खिलाड़ी हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो उनकी अपनी एक अलग पहचान है। आदिवासियों को तराशने की जरूरत है, अगर ठीक से उनको तराशा गया तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय और ओलिंपिक में भी मेडल ला सकते हैं। इस अवसर पर अनुराग जैन और सौरभ लुनिया ने भी सभी तीरंदाजों शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय हैं कि सब जूनियर और पैरा आर्चरी के नेशनल टूर्नामेंट आगामी दिनों जयपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ होने जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ के तीरंदाज खिलाड़ी भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।

ये रहे विजेता

ब्वायस इंडियन राउंड : प्रियांशु मरकाम प्रथम, हरेंद्र प्रकाश द्वितीय, युवराज यादव तृतीय।

ब्वायस गर्ल्स राउंड : जया साहू प्रथम, भूपेंद्री पोर्ते द्वितीय, नंदनी पोर्ते तृतीय।

ब्वायस रिकब राउंड : गितेश यादव प्रथम, श्रीयांश वर्मा द्वितीय, संजय सोनवानी तृतीय।

गर्ल्स रिकब राउंड : फलक प्रथम, माही जांगड़े द्वितीय, विनीशा मिंज तृतीय।

ब्वायस कंपाउंड राउंड : निशांत पटेल प्रथम, रुस्तम द्वितीय, अर्क तृतीय।

ब्वायस कंपाउंड राउंड: अदिति साहू प्रथम, पद्मा द्वितीय, आर्या तृतीय ।

किसान दिवस : छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी

रायपुर। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने और उनकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में किसान दिवस का बड़ा महत्व है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है।

छत्तीसगढ़ कृषि संचालनालय के मुताबिक राज्य में लगभग 37 ।46 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 138 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46 ।51 लाख हेक्टेयर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 34 प्रतिशत है। प्रदेश में 58040 वर्ग किलोमीटर (42 ।93 प्रतिशत) में कृषि की जाती है।

छत्तीसगढ़ में धान, सोयाबीन, उड़द और अरहर प्रमुख खरीफ फसलें हैं। जबकि रबी सीजन में मुख्य रूप से चना और दूसरे दलहनी फसलों की खेती होती है। राज्य के कुछ जिलों में गन्ने की अच्छी फसल होती है। प्रदेश में चार सहकारी चीनी मिलें हैं। यहां की अन्य फसलें मक्का, बाजरा, मूंग, गेहूं, मूंगफली हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी इलाकों को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य को तीन कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कृषि-जलवायु क्षेत्रवार क्षेत्र, मिट्टी, सिंचाई के अनुसार खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ ने दोहरी फसल वाले क्षेत्रों को बढ़ाने, फसल पैटर्न में विविधता लाने और कृषि आधारित लघु उद्योगों से आय में सुधार करने के लिए एक ठोस योजना शुरू की गई है। कृषि क्षेत्र की क्षमता को और बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 32 प्रतिशत है।

सीएम विष्णुदेव साय ने किसान दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के नेता, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया।

मंदिर हसौद शाखा के 7 केन्द्रों में 33 लाख कट्टा धान जाम

रायपुर। केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक रायपुर के मंदिर हसौद शाखा के अधीन बनाये गये 7 धान उपार्जन केन्द्रों में बीते रविवार की स्थिति में लगभग 33 लाख कट्टा धान परिवहन के अभाव में जाम पड़ा है। इसके एक केन्द्र टेकारी में तो अब तक खरीदे गये धान तकरीबन 52 हजार कट्टा उठाव के बोहनी के इन्तजार में है।

गनौद केन्द्र में अब तक खरीदे गये धान का महज 10 प्रतिशत के करीबन उठाव हुआ है और यहां पर लगभग 78 हजार कट्टा धान जाम है। गोढ़ी में खरीदे गये धान में से महज 30 प्रतिशत का ही उठाव हुआ है और करीबन 77 हजार कट्टा धान परिवहन के इन्तजार में है। पलौद केन्द्र में भी लगभग 30 प्रतिशत धान का उठाव हुआ है व लगभग 50 हजार कट्टा धान जाम पड़ा हुआ है। उमरिया केन्द्र में लगभग 15 प्रतिशत धान का उठाव हो तकरीबन 45 हजार कट्टा धान परिवहन हेतु प्रतीक्षारत है। बरौदा केन्द्र में लगभग 49 प्रतिशत धान का परिवहन हो चुका है और महज 5 हजार कट्टा धान का उठाव बाकी है। सर्वाधिक परिवहन रायपुर - आरंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मंदिर हसौद केन्द्र से लगभग 60 प्रतिशत हुआ है और करीबन 26 हजार कट्टा का उठाव बाकी है। इन खरीदी केन्द्रों का दौरा कर किसानों व कर्मियों सहित कई केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारी से चर्चा करने के बाद यह जानकारी देते हुये किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने कहा है कि जाम धान की वजह से कई केन्द्रों में खरीदी हेतु जगह नहीं होने से धान खरीदने व बेचने में कर्मियों व? किसानों को दिक्कत आ रही है पर शासन - प्रशासन के दबाव में जबरिया धान खरीदी का काम चल रहा है व परिवहन में विलंब होने से सूखती की शिकायत भी शुरू हो चला है।

सनी लियोनी के नाम पर ले रहा था महतारी वंदन योजना के रुपये

■ बैंक खाता सीज, एफआईआर

रायपुर। अभनपुर विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन बघेल ने रविवार को अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार सनी लियोनी को हर महीने 1000 रुपये जारी कर रही है। यह मामला सरकारी भ्रष्टाचार उजागर करता है। कांग्रेस नेता जयवर्धन बघेल ने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने सनी लियोन का नाम और हर महीने ट्रांसफर होने वाली राशि की जानकारी दी है।

इस पोस्ट में जो हितग्राही से संबंधित जानकारी दी गई है, उसमें पंजीकृत आवेदक का नाम सनी लियोनी है। इसका पंजीयन क्रमांक एमवीवाय 006535575 है। पति का नाम जॉनी सिंस है। इस आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार, सनी लियोनी का पता बस्तर के तालूर क्षेत्र का है और उनका आवेदन आंगनबाड़ी के माध्यम से दर्ज किया गया था। इस खाते में मार्च से हर महीने ?1000 की राशि डाली जा रही है। खाता एसबीआई में है और उसका अंतिम का 5 अंक 76531 है। इस महीने भी उनकी राशि ट्रांसफर की गई है।

रविवार को जैसे ही ये खबर मीडिया में सुर्खी बनी, कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विष्णुदेव साय सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के 70 लाख में से 50 लाख से ज्यादा में गड़बड़ी है। मृत लोगों को पैसा दिया जा रहा है। सरकार को इसकी बारीकी से जांच करनी चाहिए। इधर भाजपा ने कांग्रेस ने इन आरोपों को सिर से नकारते हुए अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी।

सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार जा ने एक्स पर पोस्ट कर इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा यह साजिश जानबूझ कर सरकार को बदनाम करने के लिए की गई हो सकती है। इस मामले को जिस तरह उछाला गया है, उससे यह आशंका है कि राजनीतिक विरोधियों ने ही यह षड्यंत्र किया होगा।

महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी के आरोपों के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने महतारी वंदन योजना में ग्राम तालुर से संबंधित अनियमितता की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों को सौंपी। उन्होंने संबंधित के बैंक खाते को सीजकर वसूली की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही मामले में संलग्न व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रविवार को संबंधितों पर कार्रवाई की।

बस्तर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मीडिया के जरिए महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी को हर महीने महतारी वंदन योजना के एक हजार मिलने की शिकायत मिली। जिसकी प्रारंभिक जांच से पता चला कि आवेदन ग्राम तालूर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है। मामले की जांच करने पर इस बात का खुलासा हुआ कि वीरेंद्र जोशी नामक व्यक्ति जालसाजी कर राशि अपने खाते में ले रहा है।

आरोपी वीरेंद्र जोशी के खिलाफ सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के अपराध में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। बैंक खाते को होल्ड कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित कार्यकर्ता और तत्कालीन पर्यवेक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही हैं।

सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन का लाभ लेने वाले कथित आरोपी वीरेंद्र जोशी ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। जोशी ने कहा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे आधार और बैंक अकाउंट नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया। वीरेंद्र जोशी ने कहा कि गांव में सनी लियोनी के नाम से कोई फॉर्म जमा नहीं किया गया। ये साइबर क्राइम हो सकता है। महतारी के नाम से कोई पैसा मेरे एकाउंट में जमा नहीं हो रहा है।

रायपुर एम्स में पद्म विभूषण तीजन बाई का इलाज शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान और देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का रायपुर एम्स में इलाज शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने तीजन बाई की बीमारी की जानकारी मिलते ही उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनसे मिलने भी पहुंचे थे और पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता भी दी थी।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था कि तीजन बाई के लिए घर में ही मोटराइज्ड रिमोट कंट्रोल आटोमेटिक बेड, बेड टेबल और व्हील चेयर उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तीजन बाई के लिए ये जरुरी उपकरण उपलब्ध करा दिया है।

एक मेडिकल आफिसर और एक फिजियोथिरेपिस्ट को भी तीजन बाई की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्टरों की टीम दिन में एक बार उनके घर में ही उनकी स्वास्थ्य जांच करके मेडिकल रिपोर्ट तैयार करती है।

पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई ने पंडवानी के जरिए छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रोशन किया है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहचान हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार भी तीजन बाई की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

खुद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं।

एक राष्ट्र-एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम

कल्याणी शंकर

भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने संसद में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' विधेयक पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बहु-प्रतीक्षित विधेयक का उद्देश्य लगभग एक अरब मतदाताओं वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इस विधेयक ने व्यापक बहस, महत्वपूर्ण रुचि और विभिन्न दलों के विरोध को जन्म दिया है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण कुछ सवालों के जवाब की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास संसद में विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत है? क्या कोई राजनीतिक सहमति है? क्या विपक्ष इसे विवादास्पद मुद्दा बनाएगा? क्या विधेयक का समय सही है? अधिकांश विपक्षी दल एक साथ चुनाव कराने के विचार को खारिज करते हैं। इनमें कांग्रेस,वामपंथी दल, तृणमूल कांग्रेस और क्षेत्रीय और छोटे दल शामिल हैं। वे इसे मुख्य रूप से राजनीतिक हिसाब-किताब चुकाने और इस आशंका के कारण खारिज करते हैं कि इससे भाजपा को फायदा हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली 9 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की थी और इसे 'गेम चेंजर' करार दिया था। 32 दलों ने इस अवधारणा का समर्थन किया जबकि 15 ने इसे अस्वीकार कर दिया। पैनल ने यह भी सलाह दी कि केंद्र इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पैनल बनाए। साथ ही, सभी चुनावों के लिए एक संयुक्त मतदाता सूची होनी चाहिए ताकि मतदाता राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों के लिए एक ही सूची का उपयोग करें। पिछले कुछ वर्षों में,चुनाव एक मानक विशेषता बन गए हैं लेकिन 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' विधेयक में हमारी चुनाव प्रक्रिया को नया रूप देने की क्षमता है। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि यह अभियान लागत को काफी कम कर सकता है। प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव कम कर सकता है और शासन को सुव्यवस्थित कर सकता है। यह अंततः चुनावों की आवृत्ति को कम करके जनता को लाभान्वित कर सकता है। एक ऐसी संभावना जो आशावादी होनी चाहिए। भारत में चुनाव विभिन्न स्तरों पर होते हैं, जिसमें सकल मूल स्तर भी शामिल है। पहला पंचायत है, उसके बाद जिला स्तर,राज्य विधानसभा स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर। ये अलग-अलग समय पर होते हैं और सरकार इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना चाहती है। मजे की बात यह है कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है। ये 1951 से 1967 तक हुए। विभिन्न सरकारों की समय से पहले बर्खास्तगी और उसके परिणामस्वरूप विधानसभाओं के भंग होने से चुनाव में देरी हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई विपक्ष शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक केवल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाकर ही कानून बन सकता है। भाजपा को सहयोगी दलों और मित्र दलों के समर्थन की भी जरूरत है। हाल ही में हुए 2024 के चुनावों में भाजपा की सदन में बहुमत से 40 सीटें कम रह गई थीं और वह केवल जद-यू और तेदेपा की मदद से ही सरकार बना सकती थी। अधिकांश विरोधी दल एक साथ चुनाव कराने को खारिज करते हैं,जिनमें कांग्रेस, वामपंथी दल, तृणमूल कांग्रेस और क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां शामिल हैं। यहां तक कि भाजपा में भी विधेयक पेश किए जाने के समय 20 सांसद अनुपस्थित थे।कोविंद पैनल ने वोटों को दो भागों में रखने का भी सुझाव दिया। पहला भाग लोकसभा और विधानसभा के लिए होगा और दूसरा भाग स्थानीय समूहों के लिए होगा। ऐतिहासिक रूप से 1952 से 1967 तक पहले चुनावों में यह एक साथ हुआ करता था। इस विधेयक के सामने महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां हैं। कोविंद पैनल ने अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है। हालांकि, भाजपा के पास इस संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं है और संविधान में समवर्ती चुनावों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

निस्तेज विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलेगा?

ललित गर्ग

विपक्ष बात-बात पर तू-तू, मैं-मैं करते हुए बात का बतंगड़ बनाकर देश का भारी नुकसान कर रहा है। संसद को चलने नहीं दे रहा है, आधे-अधूरे बयान के हिस्से को प्रचारित कर घटिया एवं सस्ती राजनीति करते हुए देश को गुमराह कर रही है। बेबुनियाद एवं भ्रामक मुद्दों को उछाल कैसे गुल खिलाये, कैसे देश को अंधेरों में धकेला जाये, इसी फिराक में कांग्रेस एवं समूचा विपक्ष दिनरात लगा है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डा. आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा, तीखी नोकझोंक एवं होहल्ला। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कह कर आंबेडकरजी का अपमान कर दिया कि यदि आंबेडकर, आंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से आंबेडकरजी का अपमान कैसे हो गया? विडम्बना देखिये कि आजादी के बाद से अब तक आंबेडकर का अपमान करने, तिरस्कार करने एवं उनकी उपेक्षा करने वाला दल एकाएक उनका इतना हिमायती कैसे हो गया? यह सारा हंगामा विपक्ष इसलिये कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी ने आंबेकडर को शीर्ष राष्ट्रनायकों में शुमार कर किया है और उनकी नीतियों, सिद्धान्तों एवं मूल्यों को राजनीति का अहम हिस्सा बनाया है। विपक्ष डरा हुआ है कि भाजपा आंबेडकर को आजादी के बाद प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के बाद उचित स्थान देकर दलित समुदाय के हितों की वास्तविक चिन्ता की है, जिससे दलित वोट भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिये शाह के बयान को तोड़-मरोड एवं आधा-अधूरा प्रस्तुत कर बेवजह का हंगामा करने पर तुले विपक्ष एवं उनके नेताओं ने जो एवं जैसे तर्क दिए हैं, वे विचित्र ही नहीं, हास्यास्पद भी हैं।

बाबा साहेब आंबेडकर पर घडियाली आंसू बहाने वाला विपक्ष एवं विशेषत: कांग्रेस यह भूल रही है कि आंबेडकर का सर्वाधिक अपमान एवं उपेक्षा इन्हीं दलों ने की है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आंबेडकर को पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि आंबेडकर मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेस नीति से नाखुश थे। उनका मत था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, अत: सभी मुस्लिम को भारत छोड़ देना चाहिए? गांधी और नेहरू ने इस विचारधारा का विरोध किया? गांधी तो विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए? बाबा साहेब ने गांधी से समझौता कर संविधान को मुस्लिम के अनुसार ड्राफ्ट कर दिया? फिर भी नेहरू बाबा साहेब के विरुद्ध लगातार लगे रहे। यहां तक आंबेडकर के चुनाव लड़ने पर नेहरू ने उनके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें हरवा दिया? विडम्बना देखिये कि आंबेडकर के सचिव नारायण सदोबा काजरोलकर को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने न केवल दो बार उन्हें चुनाव में हराया बल्कि केन्द्र सरकार में उनकी घोर उपेक्षा लगातार जारी रखी। इसी से नाराज होकर आंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तिफा देते हुए नेहरू पर गंभीर आरोप लगाये। इतना ही नहीं आंबेडकर ने स्वयं के बनाये संविधान को जला देने की बात भी इसलिये कही थी कि संविधान का संचालन गलत हाथों में है।

इतिहास की इन त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों के बावजूद आखिर कांग्रेस किस आधार पर आंबेडकर की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में विरोध कर रही है। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि डा. आंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही नागवार गुजरा और इसी कारण वह संसद के भीतर-बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। इसे तूल देने के लिए उसके नेताओं की ओर से संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा बरपाया कि दोनों दलों के सांसदों के बीच मकर द्वार पर धक्कामुक्की में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट देखी गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो मेरे ऊपर गिरे। आरोप पर जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि हां! ऐसा हुआ। वे हमें प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश रहे थे। ये तर्क एवं त्रासद स्थितियां संसदीय गरिमा को धुंधलाने वाली है। कांग्रेस के तर्कों का स्तर न केवल राजनीतिक विमर्श का गिराने वाला ही नहीं, बल्कि यह बताने वाले भी हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस भाजपा के बारे में तथ्यहीन एवं भ्रामक अफवाहें फैला रही है। कांग्रेस नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक गरीब और बेरोजगारी का गीत गाते रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में न तो गरीब खत्म हुए और न बेरोजगारी? नीयत में खोट और अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय हो जाता है, तो ऐसी हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। भारत की राजनीति में इस समय यही स्थिति बन गई है।

राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछलादार, स्तरहीन एवं बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। झूठ को जोर-जोर से चिल्लाकर कहने से वह सच नहीं हो जाता। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक यह कहना उचित समझा कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि आंबेडकरजी का अपमान हो गया, संविधान खतरे में आ गया इसलिये गृहमंत्री को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए। आखिर इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डा. आंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवनकाल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, लेकिन आंबेडकरजी को यह सम्मान दशकों बाद 1990 में मिल सका। यहां तक संसद के केन्द्रीय कक्ष में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं इन्दिरा गांधी की तस्वीरें तभी लग गयी लेकिन आंबेडकर की तस्वीर वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री रहते लगायी गयी। क्या कांग्रेस बता सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों आंबेडकर की लगातार उपेक्षा होती रही? डा. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा, यह आगे चलकर उसे चलाने वालें सत्ता नेतृत्व की मानसिकता एवं नीयत पर निर्भर करेगा। 1975-77 में यह शब्दश: सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ अत्याचार करते हुए आपातकाल लागू किया गया, जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। लेकिन आज जो संविधान बचाने का शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद से संभल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जनता को गुमराह करने की कुचेष्टा मात्र है। निश्चित ही यह दयनीय, विडम्बनापूर्ण एवं त्रासद है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब घातक उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदरभाव प्रकट करते हैं, न ही आंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज हमारे विपक्ष के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस स्थिति से देश को बाहर निकाल सके, राष्ट्रीय चरित्र को जीवित रखने का भरोसा दिला सके। प्रश्न है कि निराश करने वाला विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलता रहेगा?

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(7) प्रतिवादी का यह आक्षेप बड़ा ही विचित्र है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो महाशय जी ने कभी महाभारत को आंख से देखा ही नहीं। यदि ऐसा न होता तो वह कभी यह कहने का साहस न करते कि महाभारत में पुराणों का नाम नहीं आता। यदि पाठक महाशय जी की उक्ति की सत्यता देखना बाहते हैं तो इसी ग्रन्थ में प्रमाणाध्याय- निर्दिष्ट महाभारत की प्रभाणावलि का एक बार फिर अवलोकन करें । कम से कम दर्जनों ऐसे प्रमाण वहाँ अङ्कित हैं कि जिन में बार 2 पुराणों का नाम आता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में पुराणों की अष्टादश संख्या का उल्लेख एवं ब्राह्म आदि पुराणों का संकेत भी स्पष्ट तया मिलता है, यथा-

[क] अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्यत्फलं लभेत् । तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय:।। (महाभारत स्वर्गारोहणाध्याय 6)

[ख] ब्राह्म हि मार्गमाक्रम्य वर्तितव्यं बुभूषता । (महाभारत अनुशासन 143।55)

जहां पहले पद्य में पुराणों की संख्या अठारह कही गई है वह दूसरे पद्य में उक्त कई अध्यायों को उपलब्ध ब्रह्मपुराण से ज्यों के त्यों उद्धृत करके उनको ब्रह्ममार्ग के नाम से स्मरण किया है।

यदि हम दुर्जनतोष न्याय से क्षणमात्र के लिए यह मान भी लें कि महाभारत में पुराणों का नाम नहीं आता और अवश्य ही वे अठारह के अठारह ग्रन्थ महाभारत के पश्चात् निर्मित हुये हैं, तब भी पुराण अर्वाचीन हैं और व्यास-कृत नहीं हैं यह कैसे सिद्ध हो जायगा ? क्योंकि प्रतिवादी के हेतु से केवल यही बोध होता है, कि अनेक ग्रन्थों के कर्ता ने अमुक ग्रन्थ प्रथम रचा और अमुक उसके बाद। जैसे स्वा. दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश पहिले रचा और संस्कारविधि उसके पश्चात, परन्तु दोनों का कर्ता तो एक ही रहा न ?

क्रमश: ...

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल इत्यादि संकटों से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इसी दिन 24 दिसंबर, 1986 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष ने इस विधेयक को तैयार नहीं किया बल्कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमत: इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान खरीदता है, वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा।

बहुत कम उपभोक्ता जानते होंगे कि उनके क्या अधिकार हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसलिये मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वह धोकाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वह इसकी शिकायत कर सकें। इस कानून में जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो के बारे में जानकारी का अधिकार एवं इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है।

उपभोक्ता दिवस मनाते हुए हम केवल उपभोक्ता अधिकारों की ही बात नहीं करते बल्कि उपभोक्ता की उन्नत एवं सम्यक् सोच को भी विकसित करते हैं। फ्रांसीसी विचारक विचारक ज्यां बोद्रियो ने आधुनिक उपभोक्तावाद की मीमांसा करते हुए कहा है कि पहले वस्तु आती है तो वह सुख देने वाली लगती है। अंत में वह दु:ख देकर चली जाती है।

पहले वह भली लगती है, किन्तु अंत में बुरी साबित होती है। आर्थिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के लिये उपभोक्ता जागृति जरूरी है। आज का उपभोक्तावादी दृष्टिकोण एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है, हिस्टीरिया की बीमारी बन गया है।

भारत-कुवैत रणनीतिक रिश्तों का अर्थ

अनिल त्रिगुणायत

पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देश कुवैत में नरेंद्र मोदी की यात्रा 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। श्रीमती इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री 1981 में कुवैत गयी थीं। उसके बाद 2009 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था। हालांकि तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे के यहां पहुंच कर इस यात्रा की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर चुके थे। जहां तक कुवैत की बात है, तो 2006 में कुवैत के अमीर भारत के दौरे पर आये थे। उसके बाद 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासन प्रमुखों के दौरे भले ही सीमित रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं।

कुवैत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास नये कुवैत के लिए जरूरी मानव संसाधन, कौशल और तकनीक है। उनकी यह टिप्पणी दरअसल कुवैत के साथ भारत के संबंधों की गहराई के बारे में बताती है। उन्होंने कुवैत में एक श्रमिक शिविर का दौरा किया, जहां 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय कामगार हैं। विदेश मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को विदेश में भारतीय श्रमिकों को सरकार द्वारा महत्व दिए जाने के रूप में पेश किया। सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विदेश में भारतीय श्रमिकों के कल्याण के लिए इ-माइग्रेट पोर्टल, मदद पोर्टल और उन्नत प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे कई कदम उठाये हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रह रहे भारतीय कामगारों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की मुहिम में योगदान करने की अपील की। फिर वह जाबेर अल-अहमद अंतराष्ट्रीय स्टेडियम में 26वें अरब खाड़ी कप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहां कुवैत के अमीर से भी उनकी मुलाकात हुई। रविवार को कुवैत के अमीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में दोतरफा संबंधों को और आगे बढ़ाने के बारे में व्यापक वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की शुरुआत में जीसीसी शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए कुवैत के अमीर को बधाई दी, तो अमीर ने कुवैत और खाड़ी क्षेत्र में एक मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की।

कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' प्रदान किया, जो इससे पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और प्रिंस चार्ल्स जैसों को प्रदान किया जा चुका है। भले ही प्रधानमंत्री के रूप में एक दशक के अपने कार्यकाल में मोदी का यह पहला कुवैत दौरा हो, लेकिन उन्होंने अपनी विदेश नीति में पश्चिम एशिया को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसका पता इससे भी चलता है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में अरब देशों के दौरे पर मात्र तीन बार गये थे। जबकि अपने 10 साल के प्रधानमंत्री काल में नरेंद्र मोदी का अरब देशों का यह 14वां दौरा है। भारत की ईंधन जरूरतें पश्चिम एशिया के देशों से ही पूरी होती हैं। पश्चिम एशिया में भारतीय कामगारों की बड़ी आबादी भी रहती है।

कुवैत की आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत (10 लाख) है, जबकि उसके श्रमबल में भारतीयों की हिस्सेदारी 30 फीसदी है। कुवैत में रहने वाले भारतीय सालाना लगभग 4।7 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जो विदेश से भारतीय समुदायों द्वारा देश में भेजी जाने वाली कुल सालाना धनराशि का 6।7 प्रतिशत है।

भारत और कुवैत के रिश्तों के महत्व का पता इसी से चलता है कि जब कुवैत के विदेश मंत्री इस महीने भारत आये थे, तब साझा सहयोग कमीशन (जेसीसी) का गठन किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 10।47 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। हालांकि इस कारोबार का ज्यादातर हिस्सा कुवैत से भारत आने वाला तेल और अन्य ऊर्जा उत्पाद थे, जबकि भारत ने पहली बार सर्वाधिक करीब दो अरब डॉलर का निर्यात कुवैत को किया। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का तीन प्रतिशत कुवैत से आयात करता है। देखने में यह हिस्सेदारी मामूली लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत कुवैत समेत पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर है। भारत ने कुवैत में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश भी किया है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा बहुत समय से विभिन्न कारणों से टल रहा था। संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश छोटे हैं। लेकिन इस समय कुवैत दो कारणों से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि वह पूरे खाड़ी क्षेत्र में मध्यस्थ का काम करता है। दूसरा यह कि इस समय वह जीसीसी यानी गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल का अध्यक्ष है।

भारत ने कुवैत के साथ अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदल लिया है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ सिर्फ कच्चा तेल लेने और उसके यहां अपने कामगारों को भेजने का रिश्ता नहीं है। दोतरफा रिश्ता इससे आगे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और तालमेल तक जाता है। इसके तहत जहां दोनों देश एक दूसरे के यहां व्यापार और निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं खाड़ी देशों में अपने हितों के लिए भारत कुवैत पर निर्भर है। कुवैत चूंकि जीसीसी का अध्यक्ष है, ऐसे में इस संगठन के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए भी भारत को कुवैत की मदद की आवश्यकता है।

मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति भी इस समय पश्चिम एशिया से भारत के संबंध मजबूत करने के अनुकूल है। अभी तक खाड़ी देशों में भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान था, जो लगातार दुष्प्रचार कर भारत को कमजोर करने की कोशिशों में लगा रहता था। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कमजोर पड़ा है और भारत-विरोधी योजनाओं पर अमल करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में, खाड़ी क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भारत के पास सुनहरा अवसर है। वैसे भी हाल के वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जैसी मजबूत छवि बनायी है, उसे देखते हुए खाड़ी देश अब पाकिस्तान के दुष्प्रचारों के आधार पर भारत के बारे में राय नहीं बनाने वाले। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे ने भारत के साथ खाड़ी के इस देश को मजबूत रिश्तों में बांध दिया है।

आज का इतिहास

1936 पहली बार जॉन लॉरेन्स ने रेडियोएक्टिव आईसोटोप दवाई का प्रयोग मरीज पर किया।
1953 न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर, तांगिवई में, एक रेलवे पुल एक लहार से क्षतिग्रस्त हो गया और एक यात्री ट्रेन के नीचे गिर गया, जिसमें 151 लोग मारे गए।
1954 लाओस को फ्रांस ने आजाद किया।
1955 NORAD Tracks सांता प्रोग्राम तब शुरू हुआ जब बच्चों ने कॉन्टिनेंटल एयर डिफेंस कमांड सेंटर को फोन करना शुरू किया, ताकि एक गलत छपे फोन नंबर के कारण सांता क्लॉज़ के ठिकाने के बारे में पूछताछ की जा सके।
1964 साइगॉन में ब्रिन्ड्स होटल में बमबारी हुई।
1966 जॉयफुल शोर 12 प्रदर्शनों के बाद मार्क हेलिंगर थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में बंद हो गया।
1968 नासा अपोलो 8 मिशन के अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स, चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए पहली बार यात्रा की, ने प्रसिद्ध तस्वीर अर्थराइज (चित्र) ली, जिसमें पृथ्वी को चंद्र सतह से ऊपर उठते दिखाया गया।
1971 पेरू एयरलाइंस एयरलाइंस इलेक्ट्रा अमेज़ॅन के हेडवाटर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, 10 दिनों के बाद जूलियन मार्गरिट कोपेके को छोड़कर सभी की मौत हो जाती है।
1973 मोहम्मद मोहम्मदुल्ला बांग्लादेश के कार्यवाहक अध्यक्ष बने।
1973 यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने वाशिंगटन, डीसी के गृह शासन को मंजूरी दे दी, जिससे निवासियों को अपने मेयर और नगर परिषद का चुनाव करने की अनुमति मिली।
1979 पहला यूरोपीय एरियन रॉकेट लॉन्च किया गया।
1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। यह हमला 1978 के सोवियत अफगान मैत्री संधि के बहाने किया गया था।
1980 साक्षियों ने इंग्लैंड के रेंडलेशम फॉरेस्ट, सफ़ोक में आरएएफ वुडब्रिज के पास आकाश में अस्पष्टीकृत रोशनी के कई बार देखे जाने की सूचना दी।
1982 केवल 850 छात्रों के एक छात्र के शरीर के साथ चमिनडे, एक होनोलूलू अवकाश बास्केटबॉल क्लासिक में स 1 स्थान पर वर्जीनिया 77-72 स्थान पर है।
1990 एक सैन्य तख्तापलट द्वारा रामसेवक शंकर को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में हटा दिया गया।
2008 युगांडा के विद्रोही समूह लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, हौट-उले जिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कांगो के कई गांवों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 400 मौतें और कई अत्याचार हुए।

अम्बेडकर के अपमान पर मचे सियासी तूफान के पूंजीवादी एजेंडे

कमलेश पांडे

लीजिए, हमारे विपक्षी नेताओं को एक और अपमानजनक मुद्दा मिल गया, ताकि संसद की जनहितकारी कार्यवाही को बाधित कर दिया जाए और सड़क से संसद तक हंगामा खड़ा करके लोगों को गोलबंद किया जाए। इससे मिशन आम चुनाव 2029 की विपक्षी राह आसान हो जाएगी। बताया जाता है कि एक संसदीय चर्चा के दौरान संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि आजकल आंबेडकर का नाम लेना सियासी फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता।

बकौल शाह, आंबेडकर-आंबेडकर-आंबेडकर क्यों कह रहे हो? आप अगर भगवान-भगवान कहेंगे तो 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में जाएंगी। बस इसी बयान को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है।

इस प्रकार विभिन्न दलों के समर्थन-विरोध और बचाव की सियासत के बीच संसद में धक्कामुक्की तक की नौबत आई गई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व उनके साथियों के विरुद्ध भाजपा नेताओं द्वारा एफआईआर तक दर्ज करवाना पड़ा। उधर, कांग्रेस ने भी भाजपा सांसदों के खिलाफ शिकायत दी है। इससे बिखरते इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी राहत भी मिल गई, क्योंकि जो नेता राहुल गांधी का विरोध करते थे, वही अब उनकी भाषा पुन: बोलने लगे।

चूंकि फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव और नवम्बर 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी वैतरणी पार करनी होगी, तो मुद्दा चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने मनमाफिक मुद्दा ढूंढ लिया। भाजपा ने अपनी नीतियों से मुसलमानों को उसके लिए बुक ही कर दिया है और भाजपा से दलितों को हड़पने के लिए वह संविधान बदलने से लेकर अम्बेडकर के अपमान तक के मुद्दे को हवा दे चुकी है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस का %दम समीकरण% दलित-मुस्लिम गठजोड़ मजबूत हो। बता दें कि इसी को मजबूत करते करते लोकजनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्व. रामविलास पासवान और उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भाजपा की गोद में जा बैठे।

वहीं, दम समीकरण की दूसरी प्रबल पैरोकार समझी गईं बसपा नेत्री और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सियासी दुर्गति आपलोग देख ही रहे हैं, जिनपर भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगते आए हैं। इसलिए इसी दम समीकरण पर अपना दावा मजबूत करते करते कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि इसी समीकरण ने लोकसभा चुनाव 2024 में उसे 10 वर्षों के सियासी दुर्दिन से मुक्ति दिलाई है।

यह बात दीगर है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनते ही उसकी सियासी सौतनों यानी इंडिया गठबंधन के साथी दलों की नींद उड़ चुकी है। इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र में दलितों के छिटकते ही विपक्षी आलोचना का केंद्रविन्दु बनी कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान को ऐसा तूल दिया और आक्रामक रणनीति अपनाई कि संसद में धक्कामुक्की कांड हो गया। इससे राहुल गांधी पुन: विपक्षी नेताओं के हीरो बनते प्रतीत हो रहे हैं।

अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे से ही दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों के बाद 2027 में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर 2028 में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को जीतने की रणनीति बनाएगी। चूंकि इसी बीच कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि विधानसभाओं के भी चुनाव इलेक्शन कैलेंडर के मुताबिक होंगे, इसलिए कांग्रेस जातिगत जनगणना के बाद अंबेडकर के अपमान को भी मुख्य मुद्दा बनाएगी। क्योंकि भाजपा भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर कांग्रेस के ऊपर तार्किक सवाल उठाती आई है।

राजनीतिक टिप्पणीकारों की बातों पर गौर करें तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी के %हत्यारोपी% हिंदूवादी नेता वीर सावरकर, और अब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराम अम्बेडकर के ऊपर हुई सियासी टीका-टिप्पणी कोई नई बात नहीं है, बल्कि नई बात तो यह है कि गांधी-नेहरू का अपमान सहते रहने वाली कांग्रेस ने

अम्बेडकर के अपमान को सियासी मुद्दा बनाकर एक तीर से दो शिकार कर रही है।

पहला तो यह कि दलितवादी दलों और ओबीसी की राजनीति करने वाले दलों से वह मुद्दे लपक चुकी है और इसी को धार दे रही भाजपा को जन कठघरे में खड़ा करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कवायद तेज कर चुकी है। अपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राममनोहर लोहिया, वीपी सिंह, लालूप्रसाद, मान्यवर कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी बाजपेयी आदि अनगिनत नेताओं के ऊपर सियासी टिपण्णी हुई, लेकिन बात का इतना बतंगड़ कभी नहीं बना।

कभी आजादी, कभी आरक्षण, कभी समता, कभी समरसता, कभी वामपंथ, कभी समाजवाद और कभी राष्ट्रवाद के सवाल पर सियासत हुई। रोटी कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की सियासत भी हुई। जय जवान, जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक के उदघोष हुए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तक की बातें हुईं। लेकिन जनता की माली हालत उबचुब करती रही। पिछले तीन दशकों में अमीरी और गरीबी की खाई हर रोज चौड़ी हो रही है।

एक और कड़वी सच्चाई यह है कि निर्वाचित नेताओं की आय रॉकेट की गति से बढ़ रही है, पर समतामूलक समाज स्थापित करने के संवैधानिक प्रयत्न नदारत रहे। क्योंकि जब भी सर्वहितकारी कुछ बात शुरू हुई तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कानूनी ढाल बना दिया गया। कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया और उनका समर्थन हासिल करके कहीं पारिवारिक राजनीति को मजबूत किया गया तो कहीं राजकोषीय लूट मचाई गई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह कि कहीं कोई प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई। या तो कानून स्वहित के अनुरूप बने या फिर परिभाषित किये गए। दुष्प्रभाव सबके सामने है। हिंसा-प्रतिहिंसा और असमानता हमारी नियति बन चुकी है।

यह कड़वी सियासी सच्चाई यह है कि सन 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध से देश में लागू %नई आर्थिक नीतियों% के दुष्परिणाम स्वरूप भारतीय संसद जनहितकारी मुद्दों से अपना पिंड छुड़ाती हुई प्रतीत हो रही है और सिर्फ पूंजीवादी एजेंडों को पूरा करने की गरज से जनमानस के बीच भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रही है। इन नीतियों को देश में लागू करने वाली कांग्रेस और फिर बाद में उसकी समर्थक बन चुकी भाजपा (स्वदेशी आंदोलन को भूलकर) ने पूंजीवादी राजनीति को इतनी हवा दी कि क्षेत्रीय सियासत ही हाशिए पर आ गई।

इसलिए क्षेत्रीय दलों को भाजपा और कांग्रेस के इस सियासी पेंच को समझना चाहिए, लेकिन ये भी इन दोनों दलों के गठबंधन के मोहरे बन चुके हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए कि सियासत के लिए जो जरूरी आर्थिक खाद-पानी चाहिए, वो सिर्फ पूंजीवादी कम्पनियां ही पूरी कर सकती हैं। आप गौर कीजिए कि 1990 के दशक से शुरू हुए कम्पनी राज के बाद जीवन चर्या कितनी महंगी होती जा रही है। मानवीय संवेदनाओं से परे सबकुछ को मौद्रिक पैमाने पर तौलने की बाजारू प्रवृत्ति ने खान-पान, दवा-दारू, रहन-सहन से लेकर परिवहन तक को महंगा कर दिया और गुणवत्ता के मामलों में भगवान भरोसे छोड़ दिया। वहीं, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा के बर्चस्व वाली संसद मजबूत कानूनों को पूंजीपतियों के लिहाज से कमजोर करती रही, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता बढ़ती चली गई। यह आज भी जारी है। समाज में रूपये के बढ़ते बोलबाला से प्रशासनिक तंत्र और अधिक भ्रष्ट हो गया। सियासत में ओबीसी, दलित व अल्पसंख्यक शब्दों के बढ़ते बोलबाला से जो जनप्रतिनिधियों की फौज संसद में आई, उन्होंने जाने-अनजाने सियासत को भ्रष्ट कर दिया। आलम यह है कि यथा राजा-तथा प्रजा और यथा प्रजा-तथा राजा का अंतर मिट चुका है। जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार और न्यायाधीशों के न्यायिक अवमानना के अधिकारों ने मीडिया के मुंह सील दिए।

देश में अब स्वस्थ राजनीतिक बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्योंकि पहले आजादी, फिर समाजवाद, उसके बाद हिंदूवाद की सियासत हुई, जिसमें अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, जातीय तुष्टिकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दलित-पिछड़ा-आदिवासी गोलबंदी, फिर इनकी आपसी सिरफुटौव्वल के बीच पूंजीवादी राजनीतिक अपनी जड़ जमाती रही और लोगों के मूलभूत रोजगार से लेकर जीवन यापन तक की नीतियां हाशिए पर चली गईं। अब जो भी दिखावटी जनहितकारी नीतियां लागू की जा रही हैं, उसके पीछे कॉरपोरेट लूट का एजेंडा सर्वप्रथम है, जिसे समझने में हमारे अधिकांश नेता व उनकी समर्थक अशिक्षित या कम शिक्षित जनता नाकाम रही है। आधार कार्ड, मुफ्त आवास, मुफ्त या कम ब्याज दर ऋण, डीबीटी जैसे जितने भी नव आर्थिक उपाय किए गए, सबका मकसद कम्पनियों को लाभ पहुंचना है। लोगों के पास काम नहीं है और सरकार एआई पर जोर दे रही है। सत्ता में मशीनीकरण के घुसपैठ से सिर्फ पूंजीवादियों का ही भला होगा।

सच कहूं तो एक देश, एक चुनाव भी उनका ही एजेंडा है ताकि छोटे छोटे दल समाप्त हो जाएं। छोटी-छोटी कम्पनियों को उनका ऑनलाइन बाजार लूट ही चुका है। इसलिए देश जनक्रांति की बाट जोह रहा है, क्योंकि वैश्विक पूंजीवादी ताकतों के इशारे पर थिरक रही भारतीय कम्पनियों से मुट्ठी भर लोगों का भला होगा, जबकि बहुत बड़ी आबादी भावनात्मक मुद्दों पर उलझी हुई है और किसी राष्ट्रीय अभिशाप से कम नहीं है। सवाल पुन: वही कि भावनाओं को भड़काकर सियासी रोटी सेंकने की कांग्रेस-भाजपा की चाल को आखिर कबतक समझेंगे हमारे क्षेत्रीय दल और जनहित की रक्षा के लिए उनपर दबाव बढ़ाएंगे, अन्यथा एक समय बाद वो भी लोगों के बीच अप्रासंगिक हो जाएंगे।

अपने राष्ट्रपिता के साथ क्या कर रहा है बांग्लादेश?

शिवेंद्र तिवारी

बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद नई सरकार लगातार पुरानी नीतियों को बदल रही है। अंतरिम सरकार ने अब अपनी मुद्रा %टका% को बदलने का एलान किया है। मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने नए करेंसी नोटों की छपाई को मंजूरी दे दी है। नए नोटों में अब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर नहीं होगी। इससे पहले बंगबंधु से जुड़े राष्ट्रीय अवकाश और कई कानूनों को भी रद्द कर दिया गया था। अवामी लीग ने इन फैसलों को बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का प्रयास बताया है। आइये जानते हैं कि बांग्लादेश ने अपनी मुद्रा को लेकर किस योजना की घोषणा की है? नए करेंसी नोटों में क्या बदलेगा? बदलाव की वजह क्या है? नई सरकार कैसे मुजीबुर्रहमान की विरासत को मिटा रही है? आने वाले समय में बांग्लादेश नए बैंक नोटों को लॉन्च करेगा। जानकारी के अनुसार, अगले छह महीनों में 20 टका, 100 टका, 500 टका और 1,000 टका कीमत के नोट बाजार में आएंगे। बांग्लादेश बैंक ने हाल ही में इस योजना की जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक की प्रवक्ता और कार्यकारी निदेशक हुस्ने आरा शिखा ने कहा कि सरकार अगले छह महीने में नए डिजाइन वाले करेंसी नोट छापेगी। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि केंद्रीय बैंक को इस संबंध में सरकार की मंजूरी मिल गई है और अब आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जानी है। मुद्रा छापने के लिए जिम्मेदार सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नोटों की डिजाइन को नया रूप देने की तैयारी है। स्थानीय मीडिया ने केंद्रीय बैंक के सूत्रों के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर अब नए नोटों पर नहीं दिखेगी। डिजाइन में शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर के स्थान पर जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के भित्तिचित्रों को जगह दी जाएगी। इसके साथ ही मजहबी स्थलों और पारंपरिक बंगाली रूपांकनों को भी नोट पर प्रदर्शित किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई डिजाइन समय के साथ सभी तरह के नोटों से बंगबंधु की तस्वीर को हटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसी महीने निविदा प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नए नोटों की छपाई शुरू हो जाएगी और अगले वर्ष जून तक इन्हें प्रचलन में लाने की योजना है। बांग्लादेश में 2 से 1,000 टका के सभी नोटों पर शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर छपी हुई है। कुछ नोटों पर दोनों तरफ उनकी तस्वीर छपी हुई है। यहां तक कि धातु के सिक्कों पर भी उनकी तस्वीर छपी हुई है। बांग्लादेश बैंक ने लोगों से कहा है कि नए नोट प्रचलन में आने के बाद भी सभी मौजूदा नोट प्रचलन में बने रहेंगे। 5 अगस्त को देश की राजधानी ढाका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर चढ़ गए थे और उसे अपवित्र किया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रदर्शनों के दौरान देश भर में शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था और उनको समर्पित संग्रहालय को आग के हवाले कर दिया गया था।

संसद की गरिमा का भी ध्यान रखें सांसद

ऋतुपर्ण दवे

मैं अपने घर पर टी.वी. देख रहा था। उसी समय एक परिचित परिवार समेत आए। साथ में छोटा बच्चा था जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। टी.वी. पर संसद की कार्रवाई चल रही थी। हंगामा, तख्तियां लहराना, नारेबाजी और बार-बार खड़े होकर बाधा उत्पन्न करने के दृश्य देखकर बच्चे के मन में एक अजीब-सी जिज्ञासा या कौतूहल जैसा कुछ था। बच्चा कभी टी.वी. देखता तो कभी मुझे। अचानक उससे रहा नहीं गया। पूछ ही लिया अंकल, ये कौन सा स्कूल है? कितना उधम करते हैं! बच्चे की जिज्ञासा और उसके मन में कौंध रहे सवाल मेरे लिए असहज थे। उसका पूछना वाजिब था लेकिन मेरे पास उत्तर नहीं था। सदन की कार्रवाई में माननीयों की रुकावटें आम-सी हो गई हैं।

लगता है कि संसद अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम होती जा रही है? क्या इससे देश की जनता में निराशा के भाव नहीं आते होंगे? पहले भी ऐसा होता रहा, आगे कब तक होगा नहीं मालूम! संसद, बहस चर्चा और असहमति का मंच हो सकता है, लेकिन व्यवधान का हरगिज नहीं। 25 नवंबर से शुरू हुए 26 दिनों के शीतकालीन सत्र में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा का बीता शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे कम उत्पादकता वाला केवल 57 प्रतिशत रहा। जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 43 प्रतिशत रही।

संविधान पर चर्चा और बाकी समय शोर-शराबा और हंगामे के नाम रहा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने की खातिर संविधान दिवस मनाया गया और चर्चा भी हुई। लेकिन संसदीय गरिमा कितनी तार-तार हुई सबने देखा। काश माननीय भी सोचते? 20 दिसंबर तक चले सत्र के दौरान दोनों सदनों में 20 बैठकें हुईं, जो 62 घंटे चलीं। यही समझ आता है कि हमारे माननीय कितने गंभीर हैं? संसद की बैठकों में लगातार कमी आ रही है। भारतीय संसद का

पहला सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया जिसमें लोकसभा की 677 बैठकें हुई थीं यानी साल भर का औसत 135 रहा। वहीं पिछली लोकसभा में साल में केवल 55 बैठकें हुईं। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला अधिवेशन हुआ। 1952 से लेकर 23 मार्च 2020 तक राज्यसभा में 945 सरकारी विधेयक पुरस्थापित किए गए। जबकि 26 दिनों तक चले सत्र में लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में 5 पेश विधेयकों में 4 और राज्यसभा में 3 विधेयक पारित हुए। लोकसभा चुनाव में सरकार, राजनीतिक दल और प्रत्याशियों का हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही और विधायी कामकाजों और नीतियों के संवेदनशील मुद्दों पर बहस कम और हो हल्ला ज्यादा होने लगा।

भले ही राज्यसभा चुनाव सीधा नहीं होता। लेकिन इसमें भी तो पैसा ही खर्च होता है। संसद चलाने में होने वाले खर्च का सही उपयोग नहीं होता है। सदन में विधायी कामकाज या कहें कि सकारात्मक नीति निर्धारण पर चर्चा कम और हो हल्ला ज्यादा होता है। सदन संचालन के दौरान हंगामे के चलते खर्चों में कमीं नहीं होती। उल्टा कुछ न कुछ बोझ बढ़ता ही है। कर्मचारियों, अधिकारियों की पगार, कार्रवाई का प्रसारण, प्रकाशन, संग्रहण के साथ संसद भवन की सुरक्षा, रख-रखाव और माननीयों की सुरक्षा पर भारी खर्च होता है। सारा बोझ सरकारी खजाने पर आता है जो कहीं न कहीं जनता ही चुकाती है। यकीनन सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। कामकाज न होने से इस बार अनुमानित नुकसान 84 करोड़ रुपए है। एक सवाल हर किसी के मन में कौंधना स्वाभाविक है कि क्या महज हंगामा फिर कार्रवाई अगली सूचना तक स्थगित करना लोकतंत्र के मंदिर में नैतिक कहा जा सकता है? लगता नहीं कि संसद युद्ध का मैदान बन गई? यहां भी हाथापाई, झूमा-झटकी और उठा-पटक की तस्वीरें आम होने लगीं।

1951-52 का कुल चुनावी खर्च 10.5 करोड़ रुपए आया। यही साल 2024 में एक लाख 35 हजार करोड़ से भी ऊपर पहुंचना अनुमानित है। सैंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी सी.एम.एस. की लोकसभा चुनाव पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 3500 से 3870 करोड़ रहा। जबकि साल 2019 में लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। संसद की कार्रवाई का प्रति मिनट खर्च लगभग अढ़ाई लाख रुपए आता है। जो एक घंटे का डेढ़ करोड़ होता है। अमूमन हफ्ते में 5 दिन कार्रवाई चलती है और रोजाना औसतन 6 घंटे कामकाज होता है। अगर यही विरोध,हो-हल्ला और शोर-शराबे की भेंट चढ़ जाएंगे तो करदाताओं के खून-पसीने से खजाने में जमा पैसे कब तक स्वाहा होते रहेंगे? क्या देश के लिए नीतियां-रीतियां और कायदे-कानून बनाने वाले हमारे माननीय इस दिशा में भी सोचेंगे?

अब नागपुर की तो सबको सुननी ही पड़ेगी?

अमिताभ श्रीवास्तव

पहले महाराष्ट्र की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार समारोह और उसके बाद विधानमंडल के शीतकालीन सत्र, फिर धीरे-धीरे सभी सत्ताधारियों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय की दौड़ ने राज्य की राजनीति में अनेक बातें साफ कर दी हैं। अब विपक्ष के दल संघ के नाम पर चाहे जितने सवाल उठा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नीत सरकार अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी और उसका मार्गदर्शक भी वही होगा, जिसने चुनाव में उसकी सहायता की है।

तभी संघ के सौ साल पूरे होने के अवसर पर एक स्वयंसेवक का तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना महज एक संयोग नहीं, बल्कि एक संगठित प्रयास माना जा सकता है। जिसके पीछे परिश्रम और रणनीति दोनों ही हैं। यद्यपि विपक्ष की भाषा में 'राक्षसी बहुमत' जहां महाविकास आघाड़ी के लिए चुनौती है, वहीं सत्ता पक्ष में बैठे दलों के लिए भी भीतरी जवाबदेही भरी चेतावनी की तरह है।

वह भी उस परिदृश्य में जब भाजपा के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के पहले राज्य में स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी की सरकार बनाने की घोषणा कर चुके हैं। एक नए घटनाक्रम में विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान गुरुवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर के रेशिमबाग स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे।

उनके साथ विधान परिषद की उपसभापति नीलम गो?हे, मंत्री संजय राठौड़, संजय शिरसाट, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत जैसे अनेक शिवसेना और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेता भी थे। सभी का एक साथ वहां पहुंचना किसी आश्चर्य से कम नहीं समझा जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचे उपमुख्यमंत्री शिंदे ने स्वयं को संघ की शाखा से तैयार हुआ बताया।

इसी प्रकार सभापति गो?हे ने खुद का वहां पहुंचना मातृभूमि में जाने की तरह बताया। इसी प्रकार के विचार अनेक नेताओं ने व्यक्त किए। इस दौरे में चौंकाने वाली बात शिवसेना नेताओं का दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार के संघ मुख्यालय आने के संकेत देना रहा। भाजपा की नेता और पूर्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस

पार्टी(राकांपा) की सदस्य चित्रा वाघ ने भी पवार का वहां जाना गलत ही नहीं, बल्कि चुनाव जीतने में संघ का श्रेय मानने की बात कही। ये बातें साफ करती हैं कि महागठबंधन केवल राजनीतिक तालमेल ही नहीं, वह विचारधारा में भी एक समान होकर आगे बढ़ेगा। यह स्थिति लोकसभा चुनाव की पराजय के बाद नई दिशा की ओर संकेत होगी। इसे गंभीरता के साथ लेने के अतिरिक्त आवश्यकता से जोड़कर भी देखा जाएगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो शिवसेना महाविकास आघाड़ी में संघ की आलोचना करने पर उतर आई थी, उसी से टूटे विधायक अब रेशिमबाग को अपनी मातृभूमि बताने से चूक नहीं रहे हैं।

वर्तमान स्थिति में यह भी सिद्ध हो चला है कि लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास के चलते 45 सीटें जीतने का लक्ष्य तो रखा ही, महागठबंधन में आरएसएस की जरूरत को भी नजरअंदाज किया गया। हालांकि उस समय महागठबंधन में विद्रोह के बाद बने दलों में एक नया जोश था। मगर वह टूट-फूट के नाम पर बनाई गई सहानुभूति की चाल के आगे मात खा गया।

वह भी इस तरह हुआ कि पराजय के मुहाने तक पहुंचने पर भी खतरे का अनुमान नहीं लग पाया। इसके बाद महाविकास आघाड़ी के बढ़े लक्ष्य ने चिंता की लकीरें मोटी कीं। यहीं संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा गया। इसीलिए चुनाव से पहले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संघ मुख्यालय गए।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के एक भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को संघ की बैठक में सहमति मिली और यहां तक कि सबसे पहले उन्हें ही महाराष्ट्र में बुलाकर चुनाव प्रचार में उतारा गया। फिर उत्तर प्रदेश के नारे से प्रचार को धार दी गई। हालांकि उस समय यह आशंका भी व्यक्त की गई कि मतों का अत्यधिक ध्रुवीकरण नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नारे को थोड़ा नरम बनाने की कोशिश की गई। मगर जो चुनाव की दिशा थी, वह मिल चुकी थी। उसके पीछे की रणनीति के रचनाकार स्पष्ट समझ में आ रहे थे। चरण-दर-चरण उनके प्रयास भी नजर आ रहे थे। यही कारण था कि जब चुनाव परिणाम सामने आए तो महागठबंधन के सहयोगियों को भी अपने अनुमान से अधिक सफलता मिलती दिखी।

विपक्ष की तो जमीन ही खिसक गई। उधर, नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस संघ मुख्यालय पहुंचे। वह मुलाकात भले ही कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन कान मंत्र तो मिला ही। साथ ही साथी दलों को उनकी अप्रत्याशित सफलता के पीछे छिपा हाथ भी दिखाई दिया। अब चुनाव की सफलता और सरकार के गठन के बाद भविष्य की रणनीति पर विचार होना स्वाभाविक है।

जिस प्रकार विपक्ष संविधान, वीर सावरकर, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों को तेजी से उछालकर अपना आधार दोबारा मजबूत बनाने के प्रयास में लगा है, उसी प्रकार राज्य का सत्ता पक्ष अपनी चुनावी सोच को अधिक धारदार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कार्य में उसे आरएसएस की अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए यदि सत्ता में साझेदारी है तो संघ मुख्यालय में सभी को सिर झुकाना होगा। जिसकी केवल भाजपा की अकेली जिम्मेदारी नहीं होगी। भविष्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। बीच-बीच में विधान परिषद की सीटें भी रिक्त होंगी। हर समय एक रेखा पर चलने और सहायता के लिए संघ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इस स्थिति में विधानमंडल का शीत सत्र अच्छी शुरुआत का साक्षी बन चुका है। अब रेशिमबाग आना-जाना महज एक औपचारिकता, परंपरा या संस्कार नहीं होगा। ये मिलने-जुलने के सिलसिले भविष्य की आवश्यकता को देखकर समझे तथा बनाए रखे जाएंगे। यह गठबंधन की राजनीति का नया रंग है, जिसमें केवल साझा सरकार और सीटों के तालमेल से ही नहीं, वैचारिक स्तर पर भी एकजुट और एकरूप दिखना होगा।

संसद की कार्य उत्पादकता का लगातार कम होना

नीरज कुमार दुबे

संसद का शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अडाणी मुद्दे को लेकर हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का सत्र अम्बेडकर मुद्दे पर हंगामे के साथ खत्म हुआ। सत्र के दौरान संविधान पर चर्चा जरूर हुई लेकिन संसदीय व्यवधान का नया रिकॉर्ड भी बना दिया गया। 20 दिनों के इस सत्र के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो आपको बता दें कि लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 57.87 प्रतिशत रही। लोकसभा इन 20 दिनों में चार विधेयक ही पारित कर पाई। राज्यसभा में तो 40.03 प्रतिशत ही कामकाज हो सका और पूरे सत्र में कुल दो विधेयक पारित हुए। बात सिर्फ विपक्ष के हंगामे की वजह से होने वाले व्यवधान की नहीं है, सरकार भी तब शर्मसार हो गयी जब एक देश एक चुनाव जैसा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जाते समय मत विभाजन के दौरान सत्ता पक्ष के ही दो दर्जन सांसद अनुपस्थित थे। क्या ऐसे ही चलेगा हमारा संसदीय लोकतंत्र? क्या इसीलिए छह महीने पहले देश की 140 करोड़ जनता ने 543 प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजा था? हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन संसद का महत्वपूर्ण समय और देश का कीमती धन बर्बाद कर रहे हैं? संसद के सत्र के दौरान भले सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने राजनीतिक हित सध गये हों लेकिन देश की जनता का और संसद की छवि को तो नुकसान हो गया है। आखिर कैसे होगी इसकी भरपाई? देखा जाये तो वर्तमान संसद का पहला सत्र भी हंगामेदार रहा था। इससे पिछली लोकसभा के भी लगभग सभी सत्र हंगामेदार रहे थे। पिछले कुछ सत्रों की कार्य उत्पादकता पर गौर करें तो जो आंकड़े सामने आते हैं वह चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं। सत्र की कार्य उत्पादकता का 45त्न, 35 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के आसपास रहने से हमारी संसदीय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हो रहे हैं। सदन में जो कामकाज होता है वो भी हंगामे के बीच होता है यानि शोरशराबे के बीच क्या नए कानून बन गए यह देश को पता ही नहीं चल पाता। साथ ही संसद के कामकाज का प्रतिशत लगातार कम होते जाने से एक सवाल और खड़ा होता है कि कौन हैं वो लोग जो हमारी संसद को विफल दर्शाना चाहते हैं? कहीं हमारी संसदीय प्रणाली को विफल कराने के लिए कोई साजिश तो नहीं की जा रही है? विपक्ष लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ का आह्वान तो कर रहा है लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश भारत में जनता के जनादेश पर निर्णय लेने वाला जो सर्वोच्च सदन है उसको चलने नहीं देता।

करियर को लेकर बोलीं ऋचा चड्ढा, 'कई बार ऐसा लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए'

बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अली फजल ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर एक खास पहचान बनाई है। दोनों ने शादी की। साथ ही अब उनकी एक बेटी भी है। कपल ने स्क्रीन लाइव प्रोग्राम में अपने फिल्मी सफर को लेकर बात की है। ऋचा और अली ने बताया कि वे निराशा की भावनाओं से कैसे निपटते हैं, उन्होंने बताया कि एक समय आया जब उन्हें लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए।

हर 6 महीने में हार माननी पड़ती है

ऋचा चड्ढा ने कहा कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर 6 महीने में हार माननी पड़ती है। उन्होंने कहा, हर छह महीने में मुझे हार माननी पड़ती है और फिर से शुरुआत करनी पड़ती है।

अली फजल ने कहा, आमिर खान के साथ वे थ्री ईडियट्स फिल्म में पहली बार नजर आईं थीं। ऋचा चड्ढा ने कहा, दिबाकर बनर्जी की फिल्म ओए लकी, लकी ओए में उन्होंने साल 2008 में पहली बार काम किया था। इसके बाद दोनों बॉलीवुड अभिनेता 'फुकरे' फिल्म में साथ नजर आए थे। इसके बाद अली को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में नजर आए थे।

निर्माता के तौर पर सामने आए कपल

वर्कफ्रंट की बात करें तो दोनों सितारे 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' को लेकर व्यस्त हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुची तलाती ने किया। फिल्म में सह-निर्माता ऋचा चड्ढा और कार्यकारी निर्माता अली फजल हैं। अगले साल वह एक फिल्म में एक्टिंग करती हुई भी नजर आएंगी। फिल्म 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है' में ऋचा अलग तरह का किरदार करने वाली हैं। फिल्म में प्रीति पाणिग्रही और केसव बिनॉय किरण के साथ कनी कुसरुति मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह 18 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है।

वरुण धवन ने बताया हिंदी सिनेमा में किन बदलावों की जरूरत, कहा- बॉलीवुड में ऐसे लोगों का दबदबा

वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म 'बेबी जॉन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। अभिनेता फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से लगे हैं। हाल ही में वरुण ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किन बदलावों की जरूरत हैं इस पर बात की। वरुण धवन को लगता है कि बॉलीवुड में इस समय ऐसे लोगों का दबदबा है, जिनकी सोच पैन इंडिया नहीं है, बल्कि वह मुंबई तक सीमित है। अभिनेता को लगता है कि कहानी कहने में एक निश्चित गहराई लाने के लिए पूरे भारत से लोगों का बॉलीवुड में शामिल होना जरूरी है।

छोटे शहरों के लोगों को भी आना चाहिए

अभिनेता ने कहा, मुझे लगता है कि मुंबई के अलावा कुछ आवाजों को अलग-अलग जगहों से आने की जरूरत है। बड़े 4-5 शहरों, टियर 2 और टियर 3 के अलावा, कुछ आवाजों को आने की जरूरत है। उन्हें वहां से आना होगा। हमें निश्चित रूप से इसकी जरूरत है।

बॉलीवुड में एंट्री लेना मुश्किल

वरुण ने आगे कहा, ₹पहले ऐसा होता था। मुझे लगता है कि अब यह थोड़ा मुश्किल हो गया है। प्रवेश करना। प्रवेश ना करना। अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्या मुझे एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहिए? क्या मुझे वहीं कुछ शॉर्ट्स निर्देशित करने चाहिए? या मुझे ओटीटी पर जाना चाहिए? विकल्प सामने आ गए हैं। वरुण ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को समय के साथ बदलाव की जरूरत को समझना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए कुछ पॉवर छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कोई जबरन घर में घुसा, किसी ने जबरदस्ती किया किस; वरुण धवन ने फैंस की हरकतें की शेयर

रिलेवेंट रहने पर दिया जोर

वरुण धवन ने प्रासंगिक बने रहने की बात पर जोर देते हुए कहा, ₹मैं असभ्य नहीं लगना चाहता, लेकिन हो सकता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शक्तिशाली पदों पर बैठे सभी लोग एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हों। वह एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। वह कई वर्षों से यही कर रहे हैं। वह केवल शीर्ष पर हैं। अब वह इसे पहचान नहीं पा रहे होंगे कि समय के साथ बदलना है। हम सभी को यह करना होगा नहीं तो हम प्रासंगिक नहीं रहेंगे। मैं भी प्रासंगिक नहीं रहूंगा।

'गेम चेंजर' के चौथा गाने पर दिल खोलकर थिरके राम चरण और कियारा

'गेम चेंजर' साल 2025 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। एस शंकर द्वारा निर्देशित, यह फिल्म 10 जनवरी को पोंगल के उत्सव के अवसर पर बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की भव्य रिलीज से पहले, निर्माताओं ने इसका चौथा गाना 'धोप' रिलीज कर दिया है। इस पैपी ट्रैक में राम चरण और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। बीट्स झूमने पर मजबूर कर देने वाले हैं।

'धोप' पर दिल खोलकर थिरके राम चरण-कियारा

गाने में राम चरण कियारा आडवाणी के साथ अपने बेहतरीन मूव्स दिखा रहे हैं। दोनों ने स्टाइलिश आउटफिट पहनकर नए जोशीले गाने से मंच पर आग लगा दी है। 'धोप' में ऑनस्क्रीन जोड़ी की बेजोड़ केमिस्ट्री और एनर्जी ने सोशल मीडिया की हलचल बढ़ा दी है। विशेष रूप से, ट्रैक के अंत में अभिनेता के सिंगल डांस मूव्स जबर्दस्त हैं।

नेटिजन्स ने दी प्रतिक्रिया

गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक नेटिजन ने लिखा, 'यूट्यूब पर इस गाने का धमाल होगा।' दूसरे ने लिखा, 'सुपर डांस स्टेप्स, राम चरण एक लीजेंड डांसर हैं।' इसके अलावा, गाने में राम चरण के बेहतरीन डांस मूव्स के कारण 'ग्रेस गॉड' शब्द भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है।

आयुष्मान और रश्मिका की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' में साथ आयेंगे नजर

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'थामा' की आधिकारिक घोषणा की। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल के साथ आयुष्मान और रश्मिका ने फिल्म के इंट्रोडक्ट्री सीन शूट किए हैं। कथित तौर पर फिल्म से नवाजुद्दीन सिद्दिकी के किरदार से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और परेश रावल ने 12 दिसंबर, 2024 को रात के शेड्यूल के साथ शूटिंग शुरू की। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा', निर्माता दिनेश विजान की हॉरर-कॉमेडी दुनिया की अगली किस्त होगी। फिल्म को अक्तूबर 2024 में ही शुरू किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई।

कहा जा रहा है कि फिल्म की टीम जनवरी 2025 में लगातार शूटिंग शेड्यूल के लिए दिल्ली में फिर से इकट्ठा हो सकती है। राजधानी में एक महीने की फिल्मांकन के बाद, वह फरवरी 2025 में ऊटी जाएंगे, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी कलाकारों में शामिल होंगे।

रिपोर्ट्स की माने तो ऊटी के जंगलों में लंबी शूटिंग की योजना बनाई गई है, क्योंकि नवाजुद्दीन के किरदार को जंगल में रहते हुए दिखाया गया है। खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर शीतल शर्मा द्वारा डिजाइन किए गए एक अनोखे लुक में नजर आएंगे। आदित्य सतपोदार के निर्देशन में बनी फिल्म 'थामा' दिवाली 2025 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना पहली बार एक साथ नजर आएंगे।

रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मना रहीं तृप्ति डिमरी? तस्वीरों ने डेटिंग अफवाहों को दी हवा

साल 2024 की सनसनी रही अभिनेत्री तृप्ति डिमरी को अक्सर अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ स्पॉट किया जाता है। दोनों कभी लंच डेट पर नजर आते है और कभी बाइक राइड का आनंद उठाते हुए। हाल ही में दोनों ने यूके कॉट्सवोल्ड्स से छुट्टियों की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। हालांकि, दोनों ने साथ में तस्वीरें पोस्ट नहीं की, लेकिन तस्वीरें में एक जैसी लोकेशन ने प्रशंसकों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं।

छुट्टियों का आनंद लेते नजर आईं तृप्ति

तृप्ति डिमरी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में वह बकरियों को खिलाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह हॉट चॉकलेट का आनंद ले रही हैं। एक अन्य तस्वीर में वह रेस्टोरेंट में पोज दे रही हैं।

सैम ने तृप्ति जैसी तस्वीरें की शेयर

वहीं, सैम मर्चेंट ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसी तरह की बकरी को खिलाते नजर आ रहे हैं। सैम ने भी उसी टेबल की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर तृप्ति ने बैठकर तस्वीर खिंचवाई थी। सैम ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी बकरियों को खाना खिलाते हुए अपनी वही तस्वीर शेयर की, जिससे यह अनुमान और भी बढ़ गया कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में मर्चेंट को सर्दियों के कपड़े पहने हुए और हाथ में ड्रिंक लिए हुए सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। दोनों के सोशल मीडिया पर एक जैसी तस्वीरें दिखने से उनके डेटिंग की अफवाहों को जोर मिलता है। हालांकि, दोनों ने अपने डेटिंग की अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

तृप्ति डिमरी का वर्क फ्रंट

अभिनेत्री के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2024 उनके लिए एक सफल साल रहा। उनकी आगामी फिल्म विशाल भारद्वाज की 'अर्जुन उस्तरा' है। फिल्म में शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में होंगे, जिसकी शूटिंग 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली है। इसके अलावा वह धर्मा प्रोडक्शंस की 'धड़क 2' में नजर आएंगी। अभिनेत्री रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल पार्क' में दिखाई देंगी।

'मैं अध्यात्म की ओर बढ़ गई, मेरी सारी इच्छाएं मर गईं', अपनी लव लाइफ पर बोलीं ममता कुलकर्णी

बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कई सफल फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के शीर्ष पर वे अचानक इंडस्ट्री से दूर हो गईं। उनका नाम ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा। दावे किए गए कि उसके साथ अभिनेत्री ने शादी रचा ली है। मगर, इस मामले में ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि उन्होंने उससे शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। कभी वे विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में थीं, लेकिन आज की तारीख में वे उसके टच में भी नहीं हैं।

अध्यात्म की तरफ किया रुख

ममता कुलकर्णी हाल ही में करीब 25 साल बाद मायानगरी लौटीं। इन दिनों वे अपनी लाइफ को लेकर खूब खुलासे कर रही हैं। ममता कुलकर्णी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने विक्की गोस्वामी के साथ 2016 में कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया। अभिनत्री ने बताया कि वे अब पूरी तरह से आध्यात्मिक राह पर हैं। अब उनके अंदर शादी और प्यार किसी चीज के लिए कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। ममता ने विक्की ललवानी के साथ इंटरव्यू में यह खुलासा किया है।

मर गईं सारी इच्छाएं

ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग्स केस में भी आया था। हाल ही में ममता ने कहा, 'मेरा ड्रग वर्ल्ड से कोई नाता नहीं। न ही मैं इन लोगों से मिली हूं। मेरा कनेक्शन विक्की गोस्वामी से था। मैं उससे प्यार करती थी।' ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें साल 1996 में ही अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ गया। उन्होंने कहा, 'मैं दुबई में थी। विक्की का कॉल आया उसने कहा यहां आओ, मुझसे मि लो । अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मैं उससे मिली और 12 साल बिताए'। इसके बाद विक्की गिरफ्तारी हो गई। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, 'मैंने सोचा था कि जब तक विक्की जेल से नहीं आएगा मैं भारत नहीं जाऊंगी, लेकिन जब 2012 में वह रिहा हुआ तब उनकी सारी इच्छाएं मर चुकी थीं।

आंतरिक आवाज सुनी और आगे बढ़ गईं

ममता कुलकर्णी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया कि इसके लिए उन्हें आंतरिक आवाज आई। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं ध्यान, तप और पूजा-पाठ की तरफ बढ़ी। एक-एक महीने मैं खाना नहीं खाती थी। मैं बिना खाने के रहती थी। मैंने भगवद्गीता, रामायण सभी वेद पढ़े। मेरे गुरू मुंबई में थे। 2000 में मैंने इंडिया छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं एक ही मुद्रा में ध्यान में बैठी रहती थी।

कुंभ स्नान के लिए आ रहीं भारत

ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, 'मैंने सोचा था कि जब तक विक्की जेल से नहीं आएगा मैं भारत नहीं जाऊंगी। फिर वह केन्या चला गया। मैं 2012 और 13 के आसपास कुंभ देखने इलाहबाद (अब प्रयागराज) आई। 10 दिन रही और फिर दुबई आ गई। विक्की के केन्या में रहने पर एक-दो बार उससे मुलाकात हुई। उस पर वहां भी आरोप थे।

फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। 2016 के बाद से मैं विक्की के टच में नहीं हूं'। अभिनेत्री ने कहा कि 2000 करोड़ रुपये के ड्रग मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद वे अब खुश हैं। ममता का कहना है कि वे पूरी तरह से अध्यात्म के रास्ते पर हैं। 2025 में भी वे कुंभ स्नान के लिए भारत आ रही हैं।

शाहरुख से अपने रिश्तों पर खुलकर बोले अभिजीत कहा- हम पति-पत्नी की तरह

अभिजीत भट्टाचार्य बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने 90 के दशक में शाहरुख खान की फिल्मों के कई शानदार गानों को अपनी आवाज दी। हालांकि, दोनों के बीच का मतभेद भी जगजाहिर रहा है। हाल ही में सिगर ने किंग खान के साथ अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को सुधारने की इच्छा जाहिर की। अभिजीत ने यह भी कहा कि उदित नारायण, कुमार सानू और अन्य गायकों के गाए गए गाने उनके गाए गए गानों की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकते।

शाहरुख के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर की बात

अभिजीत ने शुभांकर मिश्रा के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर अपने और शाहरुख खान के रिश्तों पर खुलकर बात की। सिंगर ने शाहरुख खान के साथ कई हिट गानों पर काम किया है, लेकिन, उनके गानों के क्रेडिट वितरण को लेकर शाहरुख खान के साथ उनका विवाद हुआ और सुपरस्टार के साथ कुछ मुद्दे थे, जिनके बारे में उन्होंने मीडिया के साथ विस्तार से चर्चा की थी। अब कई वर्षों बाद गायक अपने रिश्तों को सुधारने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख और वह एक-दूसरे के लिए आदर्श हैं, जो उनकी केमिस्ट्री और सफल सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगीत के लिए उनका मिलना बहुत जरूरी है।

अभिजीत ने कहा हम पति-पत्नी की तरह

अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा, हम पति-पत्नी की तरह एक-दूसरे के लिए बने हैं। गायक ने यह भी दावा किया कि खान के अन्य गायकों द्वारा बनाए गए नए गाने उनके द्वारा बनाए गए गानों की तरह नहीं हैं। गायक ने यह भी बताया कि ऐसा माना जाता है कि उदित नारायण या कुमार सानू सहित किसी भी गायक के गाने उनके गानों के बराबर नहीं हो सकते। अभिजीत ने कहा, क्या आपको उनके हाल के गाने याद हैं? मेरे बाद, उदित नारायण और कुमार सानू ने उनके लिए गाया, लेकिन गाने कुछ कुछ होता है या डर के बराबर नहीं थे।

शाहरुख से नहीं थे अच्छे संबंध

अभिजीत ने आगे बताया कि उनके और शाहरुख खान के बीच कभी बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं रहे और वह म्यूजिक लॉन्च या उनकी फिल्मों से संबंधित अन्य कार्यक्रमों में मिले, क्योंकि वह बॉलीवुड पार्टियों में शामिल नहीं होते हैं। सिंगर ने शाहरुख खान की कई हिट फिल्मों के लिए हिट गाने गाए हैं, जैसे 'मैं हूं ना' से तुम्हें जो मैंने देखा, 'चलते-चलते' से 'तौबा तुम्हारे इशारे' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' से 'जरा सा झूम लूं मैं'।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भर्ती अभियान 'रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते एक, डेढ़ साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा, आज भारत का युवा, नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया।

आप जीत गई तब भी केजरीवाल नहीं बन सकते सीएम : दीक्षित

नईदिल्ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। दीक्षित ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शीर्ष पद के लिए किसी को भी चेहरा बना सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जब लोग वोट देने जाएं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वे एक विधायक को चुनने जा रहे हैं, न कि भावी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसके पास फैसलों को मंजूरी देने की शक्ति होगी। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन शर्तों पर केजरीवाल को जमानत दी गई है, उन्हें देखते हुए वह फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या कार्यालय नहीं जा सकते। इसलिए, जब वह बाहर आए तो उन्हें किसी को सीएम नियुक्त करना था और इसलिए आतिशी को यह पद दिया गया।

एनडीए बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा : सम्राट

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में सस्पेंश के बीच उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए अगले साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब उनसे उन अटकलों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) चुनाव में कुमार को अपने नेता के रूप में पेश करने पर पुनर्विचार कर सकता है, तो उन्होंने कहा, कोई भ्रम नहीं है। वह एक समाचार चैनल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया साक्षात्कार का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए बिना चुनाव में जा सकता है जैसा कि उसने हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ी सफलता के साथ किया था।

सत्ता के लिए हैं एक साथ वैचारिक कारणों से नहीं : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ हैं, न कि वैचारिक समानता के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद ही सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार में शामिल लोग कितना भी कहें कि वे वैचारिक कारणों से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। अभिभावक मंत्री पद के आवंटन के संबंध में चल रही चर्चा पर बोलते हुए, एक महीने पहले सरकार बनने के बाद भी पोर्टफोलियो आवंटन में देरी की ओर इशारा करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

भाजपा सांसदों को अस्पताल से मिली छुट्टी

नईदिल्ली। संसद परिसर में गतिरोध के दौरान घायल होने के पांच दिन बाद भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को सोमवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुरुवार को विपक्ष और सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों के बीच हाथापाई के बाद सांसद घायल हो गए। ओडिशा के प्रताप सारंगी (69) और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को संसद से अस्पताल लाया गया था। हालाँकि जब सारंगी को लाया गया तो उनका बहुत अधिक खून बह रहा था, लेकिन एमआरआई और सीटी स्कैन में कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं दिखी। दोनों को आईसीयू में निगरानी में रखा गया और शनिवार को निजी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉ. शुक्ला के अनुसार, जब सारंगी को लाया गया तो उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शुक्ला ने कहा, उनके (सारंगी) माथे पर गहरा घाव था और उसे टांके लगाने पड़े।

आप सरकार के खिलाफ भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र

■ अनुराग ठाकुर बोले- केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैंबर

नईदिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा कि आप सरकार ने यमुना नदी को इतनी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है, यह इतनी दुर्गंधयुक्त, झागदार और जहरीली हो गई है। मुझे याद है, 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वह लोगों के साथ इसमें डुबकी लगाएंगे यमुना नदी, यानी 2025 के चुनाव से पहले।

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि केजरीवाल जी, 10 साल बीत गए और 2025 आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्या यमुना की सफाई हुई? क्या यमुना साफ हो गई? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को गैस चैंबर बनाने का काम किया है। इस दौरान ठाकुर ने प्यार मोहब्बत कसमें वादे गाने को गुनगुनाते हुए कहा कि देश मे सबसे महंगा पानी दिल्ली में मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में दिल्ली को लूटने और अपने घरों को भरने का काम किया है। आज दिल्ली में जनता के कामों की कोई सुनवाई नहीं है, मगर इनके नेताओं की विलासिता में कोई कमी नहीं है।

अनुराग ठाकुर ने विभिन्न नागरिक मुद्दों से निपटने के लिए केजरीवाल प्रशासन की आलोचना की, जिसमें पुराने राजेंद्र नगर में बारिश के कारण बाढ़ के कारण हाल ही में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की दुखद मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय, हमने उनकी लापरवाही के कारण युवाओं की जान जाते देखी है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इन भावनाओं को दोहराया। उन्होंने शहर की जल निकासी व्यवस्था की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला और आप पर सार्वजनिक कल्याण पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि आप सरकार नालों को साफ करने में विफल रही है, जिससे गंभीर बाढ़ आई और लोगों की जान चली गई। उन्हें केवल अपने फायदे की परवाह है। आरोप पत्र में आप के प्रमुख पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी बात कही गई है और हाल की घटनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। भाजपा नेताओं ने जनता से केजरीवाल सरकार को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया और आगामी चुनावों में जनादेश मिलने पर महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा किया।

भाजपा के आरोप पर केजरीवाल का पलटवार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। हालांकि, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उन्हें दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में दिल्ली के लिए क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप ने दिल्लीवासियों के लिए बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा, सड़क और कई अन्य चीजों के मामले में बहुत काम किया है। इन लोगों ने क्या काम किया है।

केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब जब वे चुनाव के लिए आए हैं, तो वे मेरे खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, चार्जशीट कमेटी के संयोजक विजेंद्र गुप्ता, रमेश बिधूड़ी, आरती मेहरा और सरदार आरपी सिंह ने आप सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट जनता के सामने ला दी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा कि आप सरकार ने यमुना नदी को इतनी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है, यह इतनी दुर्गंधयुक्त, झागदार और जहरीली हो गई है। मुझे याद है, 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वह लोगों के साथ इसमें डुबकी लगाएंगे यमुना नदी, यानी 2025 के चुनाव से पहले। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि केजरीवाल जी, 10 साल बीत गए और 2025 आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्या यमुना की सफाई हुई? क्या यमुना साफ हो गई?

विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर मणिशंकर अय्यर का दावा, कहा-

मुखिया पद छोड़ने के लिए तैयार रहे कांग्रेस

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेतृत्व को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का मुखिया पद छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी इसका नेता बनना चाहता है, उसे बनने दिया जाए। ममता बनर्जी में यह योग्यता है और गठबंधन के अन्य दलों के लोगों में भी यह योग्यता है।

एक मीडिया संगठन को दिए साक्षात्कार में पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे गठबंधन के नेता को लेकर परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस नेता की भूमिका हमेशा अहम रहेगी। चाहे वह पार्टी के अकेले रहने में हो या फिर इंडिया ब्लॉक में। गठबंधन में भी कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष से ज्यादा कांग्रेस नेता के रूप में सम्मान मिलेगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था। भाजपा की सीटें कम हुईं तो विपक्षी गठबंधन में जोश दिखा। मगर जैसे-जैसे राज्यों के चुनाव हुए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद शुरू होने लगे। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब कई पार्टियां गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने लगी हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। वरिष्ठ विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था।

गृह मंत्री शाह की आलोचना करना पड़ा भारी!

जयंत चौधरी की पार्टी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को हटाया

लखनऊ। केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में साझेदार राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। जयंत चौधरी ने पार्टी के अपने सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी द्वारा जारी एक चिट्ठी में इस बात की जानकारी दी है। दरअसल, बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पार्टी प्रवक्ता ने अलोचना की थी। इसी के बाद यह फैसला लिया गया है।

विज्ञप्ति में लिखा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं एवं उत्तर प्रदेश के सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभानव से निरस्त किया जाता है। इससे पहले राज्यसभा में बीआर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आरएलडी के यूपी प्रवक्ता कमल गौतम, जो दलित समुदाय से हैं, ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शाह की टिप्पणियां अनुचित थीं और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

गौतम ने कहा कि डॉ. अंबेडकर लाखों लोगों के लिए न्याय और समानता के प्रतीक हैं। अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणियां अनुचित हैं। उनकी (अंबेडकर) आलोचना करना उन लोगों का अपमान है जो उनकी पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गौतम ने आगे कहा, 卐आरएलडी किसी विरोध प्रदर्शन की योजना नहीं बना रही है। लेकिन बीजेपी के साथ हमारे गठबंधन का मतलब डॉ. अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणियों का समर्थन करना नहीं है।卐 इस बीच, आरएलडी के राज्य महासचिव अजीत राठी ने बताया था कि कमल गौतम द्वारा दिया गया बयान उनकी निजी राय है और इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी : यूएई में होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

नईदिल्ली। आईसीसीचैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचों की तारीखे सामने आ गई है। भारत आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैच यूएई में खेलेगा। यह निर्णय पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा पाकिस्तान में यूएई के वरिष्ठ मंत्री और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शेख नाहयान अल मुबारक से मुलाकात के बाद लिया गया। आधिकारिक रूप से आईसीसी ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है।

हालांकि, खबरें सामने आई है कि भारत बनाम पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी, रविवार को होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को मेजबान पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। टूर्नामेंट 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच के साथ शुरू होने वाला है। टीम इंडिया अगले दिन, संभवत: दुबई में, बांग्लादेश के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी।

ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जबकि भारत के खेलों के अलावा, चैंपियंस ट्रॉफी मैचों की मेजबानी के लिए अंतिम रूप से स्थान तय किए गए हैं - लाहौर, कराची और रावलपिंडी। दो सेमीफाइनल 4 मार्च (बिना रिजर्व डे के) और 5 मार्च (रिजर्व डे के साथ) के लिए निर्धारित हैं। फाइनल 9 मार्च को होगा और इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि एक अस्थायी व्यवस्था यह भी की गई है कि पहला सेमीफाइनल यूएई में तभी खेला जाएगा जब भारत क्वालीफाई करेगा और फाइनल के मामले में भी यही स्थिति है। 9 मार्च (रविवार) को होने वाला फाइनल मुकाबला लाहौर में होगा, अगर भारत वहां तक पहुंचता है तो इसे यूएई में आयोजित करने का प्रावधान है। आईसीसी द्वारा जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा निफ्टी 23,753 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार (23 दिसंबर) को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी दर्ज की गई। पिचले पांच ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट के बाद निवेशकों ने आज राहत की सांस ली। इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली के साथ मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी के चलते शेयर बाजार आज चढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार (23 दिसंबर) को 400 से ज्यादा अंक चढ़कर 78,488.64 पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान यह 900 अंक तक चढ़ गया था। अंत में सेंसेक्स 0.64% या 498.58 अंक चढ़कर 78,540.17 पर क्लोज हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.70% या 165.95 अंक की बढ़त लेकर 23,753.45 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की 39 कंपनियों के शेयर हरे जबकि 11 के शेयर लाल निशान में बंद हुए।

रक्षा मंत्रालय से लार्सन एंड टुब्रो को मिला बड़ा ऑर्डर

नईदिल्ली। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने रक्षा मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अंतर्गत एलएंडटी भारतीय सेना को के9 वज्र-टी ऑर्टिलरी प्लेटफॉर्म की सप्लाई करेगी। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी। इस ऑर्डर के खबर के बाद एलएंडटी के शेयरों में तेजी देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में शेयर 1.6 फीसदी तक उछल गया। कंपनी के प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन के मुताबिक, 'बड़ा' ऑर्डर 5,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच है। के9 वज्र-टी एक 155 मिमी, 52-कैलिबर ट्रैक वाला ऑटोमैटिक आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है, जिसे दक्षिण कोरियाई ऑटोमैटिक हॉवित्जर के9 थंडर से अपनाया गया है। कंपनी ने बताया कि इस ऑर्टिलरी प्लेटफॉर्म को एलएंडटी और हनवा एयरोस्पेस की ओर से डेवलप किया गया है।

सेबी ने रोकी भारत ग्लोबल डेवलपर्स कंपनी की ट्रेडिंग

नईदिल्ली। कंप्यूटर हार्डवेयर और उपकरण उद्योग से जुड़ी कंपनी भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयरों में सोमवार को बाजार खुलते ही 5% का लोअर सर्किट लग गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उसके शेयरों की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर बढ़ती शिकायतों और शेयरों में असामान्य गतिविधियों की जांच के बाद सेबी ने यह फैसला लिया। इसके अलावा 17 व्यक्तियों के शेयर बाजार में कामकाज पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बीएसई पर कंपनी के शेयर का भाव 1236.45 रुपए था। भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयर ने पिछले एक साल में 25 गुना उछाल दर्ज किया। इस तेजी के कारण कंपनी का मार्केट कैप रू. 12,500 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी। वित्तवर्ष 23 तक कंपनी की आय शून्य थी और प्रमोटरों की हिस्सेदारी भी नहीं थी।

जानबूझकर लोन न चुकाने वालों पर आरबीआई सख्त

नईदिल्ली। जानबूझकर लोन न चुकाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने में देरी न करें। बैंकों ने ऐसे ग्राहकों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए अधिक समय मांगा था लेकिन आरबीआई ने उनकी मांग खारिज कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट किया है कि जो लोग लोन लेकर जानबूझकर उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाए ताकि लोन की रकम की वसूली की जा सके। विलफुल डिफॉल्टर ऐसे कस्टमर होते हैं, जो लोन चुकाने की क्षमता रखने के बावजूद, जानबूझकर भुगतान करने से बचते हैं।

ट्रंप के टैरिफ युद्ध से बचने की चीनी जुगत और भारत

श्याम सरन

चीन की सालाना सेंट्रल इकनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस (सीईडब्ल्यूसी) आम तौर पर साल के आखिर में होती है। इसका बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इससे पता चलता है कि चीनी नेतृत्व को गुजरते साल में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा लगा और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगा।

इस साल सीईडब्ल्यूसी 11-12 दिसंबर को हुई, जब डॉनल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अमेरिका की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इससे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की बैठक हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य के लिए नीतियों की दिशा पर फैसला लिया गया। सीईडब्ल्यूसी में इन उपायों पर विस्तार से बात की गई मगर पहले की ही तरह बारीकियां नहीं बताईं। कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल प्रतिकूल होने की बात तो कही गई है मगर अमेरिका में ट्रंप सरकार द्वारा शुल्क लगाए या बढ़ाए जाने से होने वाले खतरों की आशंका पर कुछ भी नहीं कहा गया।

2023 की सीईडब्ल्यूसी बैठक से तुलना करें तो इस बार कुछ उल्लेखनीय बिंदु नजर आते हैं। पहला, मांग में ठहराव और बिगड़ती बाहरी आर्थिक चुनौतियों के बीच चीनी अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी की बात स्वीकार करते हुए नेतृत्व ने अधिक बड़े आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता चुना। पहले उसका जोर 'दूरअंदेशी भरी मौद्रिक नीति' और 'व्यापक बदलाव के बजाय चुनिंदा हस्तक्षेप' पर था मगर अब उसकी जगह 'उदार मौद्रिक नीति' पर रजामंदी बन गई है।

इसका मतलब है ब्याज दरें कम रहेंगी, बैंकों की रीपो दर भी कम रहेगी और लंबी

अवधि के सरकारी बॉन्ड अधिक मात्रा में जारी होंगे। पिछली बार यह शब्दावली वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट के दौरान इस्तेमाल हुई थी, जब चीन ने अर्थव्यवस्था बचाने के लिए 600 अरब डॉलर का भारीभरकम राहत पैकेज जारी किया था। उस समय के लिहाज से यह रकम बहुत बड़ी थी। वह पैकेज मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा निवेश के लिए था मगर इस बार का पैकेज देश के भीतर मांग और उपभोग व्यय बढ़ाने के मकसद से लाया गया है।

दूसरा, राजकोषीय नीति के मामले में चीन लीक पर चलने वाला रहा है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत की अनौपचारिक सीमा के भीतर ही रखता आया है। हाल के वर्षों में पहली बार राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी को स्वीकार किया जा रहा है। खबर हैं कि 2025 में देश का राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत रह सकता है।

तीसरा बिंदु यह है कि प्रोत्साहन के अधिक महत्त्वाकांक्षी उपाय करने के बाद भी तकनीक के बल पर उच्च गुणवत्ता वाली वृद्धि हासिल करने के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के पसंदीदा मॉडल पर बैठक में एक बार फिर मुहर लगाई गई है। नए प्रकार के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक नीति जारी रहेगी, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से वृद्धि पाने पर जोर रहेगा। चौथा, 2023 में सीईडब्ल्यूसी बैठक में 'समस्याओं से निपटने के बजाय विकास को प्राथमिकता' देने पर जोर दिया था। इस बार भी आर्थिक वृद्धि ही 'शीर्ष प्राथमिकता' है मगर अब 'विकास की रफ्तार और गुणवत्ता के बीच संतुलन' होना चाहिए। निचोड़ यह है कि शी चिनफिंग अर्थव्यवस्था के नए उच्च तकनीक से चलने वाले क्षेत्रों के विकास की खातिर उच्च वृद्धि दर को कुछ समय के लिए त्यागने को राजी हैं।

रिपोर्ट में शी की पसंदीदा योजना बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का कोई जिक्र नहीं है। शी ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक समेत 10 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के प्रमुखों के साथ 10 दिसंबर को जो बैठक की थी, उसमें देश की आर्थिक सेहत को ट्रंप से होने वाले खतरों की चीनी चिंता ही केंद्र में रही।

क्रमशः ...

विष्णुराज में ही भ्रष्टाचारियों पर हो सकती है कार्रवाईः केदार

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं पंचायत मंत्री सिंहदेव के पत्र दिखाकर भाजपा प्रवक्ता ने लगाया आरोप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बस्तर में एक फिल्मी हीरोइन के नाम से महतारी वंदन की राशि जमा होने का मामला उजागर होने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने आम आदमी की आवाज पर, समाचार पत्रों की आवाज पर कार्रवाई की, जबकि भूपेश बघेल के कार्यकाल में तो कांग्रेस की सरकार ने केवल भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण ही दिया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में कहा कि कांग्रेस पार्टी आज महतारी वंदन योजना को लेकर हाय-तौबा मचा रही है। लेकिन कांग्रेस को पता होना चाहिए कि यह विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन है जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह मामला 1000 रुपए का ही क्यों न हो। महतारी वंदन योजना में जिन अपात्र लोगों खाते में पैसा जाता था, उसके एक मामले से जुड़े दोषी को पकड़ लिया गया है और ऐसे मामलों की पतासाजी भी करेगी। भाजपा प्रवक्ता श्री गुप्ता ने तात्कालिक मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को दिखाते हुए कहा कि प्रदेश को यह अच्छी तरह याद है कि जब पिछली भूपेश सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने तत्कालीन कलेक्टर पर डीएमएफ घोटाले का आरोप लगाया था, तब भूपेश बघेल कार्रवाई करने के बजाय उक्त कलेक्टर के संरक्षण में खड़े हुए और उपहार में उन्हें बड़ा जिला दे दिया। आखिर में ईडी की कार्रवाई में घिरने पर गिरफ्तार हुई और आज तक उक्त कलेक्टर को जमानत तक नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा में कोंडागाँव जिले में डीएमएफ घोटाले का खुलासा किया तो बजाय कार्रवाई करने के मोहन मरकाम को ही अपमानजनक ढंग से प्रदेश अध्यक्ष पद से चलता कर दिया था। श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखा कि हम गरीबों का आवास नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अपने विभाग से सिंहदेव ने इस्तीफा भी दे दिया क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा होने के कारण आवास देने से मना कर दिया और अपने पंचायतमंत्री का इस्तीफा ले लिया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नीयत अगर अच्छी होती और अगर किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते तो भाजपा उस गरीब को जरूर प्रधानमंत्री आवास देती। भाजपा ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास देने के लिए कहा और प्रदेश में सरकार बनते ही भूपेश सरकार में लंबित प्रधानमंत्री आवास को बनाने की स्वीकृति भी दे दी और आज 8 लाख गरीब हितग्राहियों को पैसा मिल गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि महतारी वंदन योजना पर प्रलाप कर रहे कांग्रेस नेता यह बात अच्छी तरह गाँठ बांधकर रखें कि प्रदेश में 'विष्णु का सुशासन' है और अपराध या भ्रष्टाचार का दोषी, चाहे वह कोई हो, पर कार्रवाई सिर्फ भाजपा सरकार में ही हो सकती है।

इस दौरान प्रेस ब्रीफ में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल एवं प्रवक्ता मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

पुस्तक-संस्कृति पर कुठाराघात !

यह सूचना पढ़कर मुझे दुख हुआ. आपको भी होगा कि डाक विभाग ने रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक सेवा बंद कर दी है. सचमुच यह सस्ती थी. कैसे प्रकाशन व्यवसाय में फर्क पड़ेगा. पुस्तक भेजने के लिए लेखक-प्रकाशक इसी सेवा का उपयोग करते थे. लेकिन अब पुस्तक रजिस्टर्ड पार्सल से भेजे जाएंगी, डाकघर से पहले से अधिक लगेगा. मुझे पता चला है कि पहले एक सामान्य पुस्तक भेजने में पहले 30 रुपए लगते थे, लेकिन अब 57 रुपए लगेंगे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है. शर्म आना चाहिए हमारी सरकार को. एक तरफ यह पुस्तक संस्कृत की बात करती है, दूसरी तरफ इस संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रही है. कायदे से तो होना यह चाहिए कि हर छपी पुस्तक को भेजना और सस्ता हो. ?30 से भी कम. लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं. इसकी बुद्धि और अधिक भ्रष्ट हुई हो सकता है ?30 की जगह ?60 लेने लग जाए.

फेसबुक के माध्यम से हम सब विरोध कर रहे हैं लेकिन क्या बहरी सरकार को सुन सकेगी? अगर सुनकर अपना निर्णय वापस ले सके तो बहुत अच्छी बात है. मैंने जब सोशल मीडिया में अपनी पीड़ा व्यक्त तो अनेक लोगों की सकारात्मक टिप्पणियां मिलीं. बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है. उम्मीद करता हूं कि पूरे देश की पीड़ा का संज्ञान सरकार ज़रूर लेगी. यह जन विरोधी कदम है. इसे जल्द से जल्द से वापस लिया जाए. मेरी पीड़ा पर अपनी सहमति जताते हुए वरिष्ठ लेखक देवेंद्र दीपक जी ने सही कहा है कि "ज्ञान परम्परा की रक्षा की बात करने वाली सरकार का ज्ञान घातक निर्णय! और वह निर्णय भी चुपचाप। बजट के समय घोषणा करती तो बात सार्वजनिक चर्चा का विषय बनती ?। प्रधानमंत्री युवकों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरी ओर उनकी सरकार पुस्तक के डाक व्यय बढ़ाती है ?। यह निर्णय पुस्तक सं्स्कृति विरोधी निर्णय है। निंदा करता हूं।" गौ भक्त फैज़ खान का सुझाव मुझे ठीक लगा कि साहित्यिक डाक पर तो विशेष सब्सिडी देकर बहुत सस्ते में ये काम करना चाहिए. घनघोर लापरवाही भी. सजग लेखक अरुणकांत शुक्ल ने बताया कि "डाक बांटने का काम ठेके पर दे दिया जा रहा है. रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट को छोड़कर सभी डाक कूड़े के ढेर जैसी पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहती हैं और फिर कबाड़ी को या फेंक दी जाती हैं." कथाकार हरिप्रकाश राठी ने भी मेरा साथ देते हुए कहा कि "एक तरफ साहित्य को प्रतिष्ठित करने की बात हो रही है , दूसरी ओर हर वह कार्य किया जा रहा है जिससे साहित्य नेपथ्य में चला जाये। साहित्यिक पतन अंततः सांस्कृतिक , सामाजिक पतन की पूर्व भूमिका नहीं तो और क्या है ? पोस्टल मूल्यों में बढ़ोतरी कोढ़ में खाज जैसी बात होगी." रंगकर्मी जितेंद्र भइया ने अपनी पीड़ा कुछ यूँ व्यक्त की कि "दुनिया में आज तक कोई सरकार जन हितैषी काम करने वाली नहीं बनी, सबके सब धन को महत्व देते हैं। यही कारण है कि आज मानवता इंसानियत शर्मनाक स्थिति से भी ज्यादा नीचे जा चुकी है और दुःख इस बात का है कि हम जिस संस्कृति संस्कारों पर गर्व करने की बात करते हैं उसी देश में सबसे ज्यादा मानवता इंसानियत का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है और उसके पीछे सीधा सा कारण है हमारी बनाई हुई व्यवस्था जो अंग्रेजों की है, जिसके बारे में राजीव भाई ने बहुत कुछ बोला है। लेकिन कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता इस पर बात ही नहीं करता। अब तो शर्म आने लगी है कि हम एक ऐसी सरकार को झेल रहे हैं जो अपने आपको राष्ट्रवादी कहती है जिसमें राष्ट्र का कहीं कोई अता-पता नहीं है। मैं अपने तो यहाँ इस सरकार के नुमाइंदों से कई बार मिला हूँ लेकिन किसी के चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी कि गाय हर जगह मर रही है, हाँ इनसे हिंदू मुस्लिम करवा लो.%%

प्रदर्शन में पूरी तरह कंफ्यूज दिखी कांग्रेसः किरण देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इस दौरान पूरी तरह कंफ्यूज दिखाई दी, कांग्रेस के अलग-अलग नेता प्रदर्शन के अलग-अलग कारण बता रहे थे। वास्तव में कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है। वह आंतरिक गैंगवार के कारण बुरी तरह पस्त है। ऐसे में अपने चरित्र के कांग्रेस अनुकूल ही अराजक होती जा रही है।

किरण देव ने सीएम हाउस के घेराव को युवक कांग्रेस के राजनीतिक दीवालिएपन की पराकाष्ठा बताते हुए कहा है कि जनता-जनार्दन द्वारा सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाने के बाद से कांग्रेस के लोग मुद्दों के संकट से जूझ रहे हैं और अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए नित-नए झूठ गढ़कर प्रलाप करते रहते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि प्रदेश का हर अन्नदाता किसान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा की प्रदेश सरकार की सुव्यवस्थित रूप से संचालित धान खरीद नीति से खुशहाल है। कांग्रेसियों को यह हजम नहीं हो पा रहा है। यह एक तथ्य है कि पिछले वर्ष रिकार्ड 147 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई थी और समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त किसानों के खाते में हस्तांतरित किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस वर्ष भी 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और सरकार दाना दाना धान खरीदेगी। श्री देव ने कहा कि प्रदेश में 14 नवम्बर से शुरू हुई धान खरीदी के तहत अब तक 63.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि इसी प्रकार कानून-व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस लगातार सफेद झूठ फैलाने में लगी है। दरअसल, आपराधिक मामलों में हो रही जाँच और गिरफ्तारियों पर कांग्रेस नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि अराजकता व हिंसा की वारदातों से कांग्रेस का कनेक्शन है। पूर्व सीएम बघेल ने अपने प्रेस वार्ता में साफ-साफ यह कहा था कि उनके मितान क्लब वाले ही अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हर तरह के अपराधों में संलग्न लोगों की शरणस्थली बनी कांग्रेस का यही राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब वह सत्ता में होती है तो आपराधिक तत्वों को प्रश्रय देकर अपने हित साधने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती है, और सत्ता से दूर रहने पर इन्हीं तत्वों को इस्तेमाल करके प्रदेश में अपराधों का सिलसिला चलाकर अराजकता फैलाने में अपनी ताकत झोंक देती है।

महिलाओं के चेहरे की मुस्कान बता रही है योजना की सफलता : पुरन्दर मिश्रा

विधायक ने पढ़ी मुख्यमंत्री की पाती, लोगों में दिखा उत्साह

रायपुर । राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू की गई महतारी वंदन योजना की सफलता उनके चेहरों की मुस्कान बता रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संचार हो रहा है। उक्त बातें विधायक पुरन्दर मिश्रा ने सुशासन सप्ताह के दौरान आयोजित विधानसभा स्तरीय महतारी सम्मान समोरोह पंडरी स्थित प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, जिससे वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। इस दौरान विधायक मिश्रा ने मुख्यमंत्री की पाती का भी वाचन किया। जिसको लेकर मौजूद लोगों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा, कि राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिनको राशि मिल रही है उसको निकाल कर अन्य बचत कार्यों में लगा रही है उसके लिए उन्हें बैंक जाना पडता है तो दो बार जाना होता है। इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक में जाकर एकबार जानकारी देनी होगी जिससे उनकी उक्त राशि सीधे उस खाते में चली जाएगी। इसके लिए उन्हें बार बार बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा।कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ भी ली गई, जिसमें उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और उपस्थित जन समूह ने यह संकल्प लिया कि वे बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे और इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

महतारी वंदन योजना के गलत भुगतान पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर । **महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश** की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो एवं पात्र महिला हितग्राही को ही योजना का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सतर्कता पूर्वक कार्य संपादित किया जा रहा है एवं ऐसे प्रकरण, जिसमें योजना का गलत तरीके से लाभ लेने के लिए फेक आवेदन किए गए है, उनकी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जा रही है।

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचना, जिसमें महतारी वंदन योजना की राशि सन्नी लिओनी के खाते में जमा होने की न्यूज प्रसारित हुई है, सही नहीं है। वास्तव में सन्नी लिओनी के बैंक खाते में महतारी वंदन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है अपितु यह वीरेन्द्र कुमार जोशी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर सन्नी लिओनी के नाम से आवेदन कर आधार एवं अन्य जानकारी अपनी डालते हुए शासकीय राशि अवैधानिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी हरकत है।

रंजीता रंजन ने भाजपा पर लगाया अपमान का आरोप

रायपुर। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पाटी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई समता, समानता और न्याय के डॉ. अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई. सतापक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की।

शिवरतन शर्मा ने राज्यसभा रंजीत रंजन से पूछे पांच सवाल

रायपुर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पर्यटन पर आए राज्यसभा सांसद पहले इन सवालों का जवाब दें, तक कोई आरोप लगायें।

अपने प्रथम प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए रंजीत रंजन ने कहा था कि नक्सली बुरे नहीं होते क्या आज भी आप अपने बयान पर कायम हैं। क्या यह संयोग है कि नक्सल मोर्चे पर सरकार को जब भी कोई बड़ी सफलता मिलती हैं, उसी समय वे उन्हें कवर देने आ जाती हैं?

रंजीत जी बताएं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारकर उन्हें जो राज्यसभा की सदस्यता मिली है, उसके साथ उन्होंने कितना न्याय किया? छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण और राज्य के विकास में आपने क्या योगदान दिया?

रंजीत रंजन जी बताएं कि आपके दो साथी राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला व के टी तुलसी जी छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते हैं।

रंजीत जी बताएं कि छत्तीसगढ़ में जब उनकी पार्टी सत्ता में रहकर लूट, भय और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर रही थी, तब तीन करोड़ छत्तीसगढ़ियों के हित में उन्होंने बघेल सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई?

हर माह 450 करोड़ का घोटाला इस योजना में किया जा रहा है

रायपुर । महतारी वंदन योजना में पहले दिन से ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महतारी वंदन योजना में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन के नाम से पिछले 10 माह से भुगतान किया जाना इस योजना की असली हकीकत को बताता है। सनी लियोन के नाम के सिर्फ एक प्रकरण का खुलासा हुआ है, हकीकत में पूरे प्रदेश में लाखों महिलाओं के नाम से प्रतिमाह फर्जी तरीके से राशि निकाल कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना भाजपा सरकार के सुनियोजित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर माह 450 करोड़ का घोटाला इस योजना में किया जा रहा है। नाम किसी का, एकाउंट किसी का 10 माह से अनवरत भुगतान बिना सुनियोजित षड़यंत्र और उच्चस्तरीय संरक्षण के संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिन 70 लाख महिलाओं को सरकार ने पात्र बताया है उन सभी के खाते में भी पैसा नहीं जा रहा है। सरकार घोषित 70 लाख में से 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही है। 45 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा रहे मतलब 45 लाख महिलाओं के नाम पर गलत लोग भुगतान प्राप्त कर रहे।

दपूम रेलवे रायपुर को मिला नराकास राजभाषा सम्मान

रायपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 67वीं बैठक आयोजित की गई । बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मानक कार्यसूची के अनुसार जुलाई-सितंबर 2024 अवधि की मंडल पर हुई राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल ने मंडल रेल प्रबंधक को बधाई देते हुए कहा कि उनकी अध?यक्षता में संचालित नगर राजभाषा कार्यान?वयन समिति, रायपुर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार का राजभाषा सम?मान प्राप?त हुआ है । 'क' क्षेत्र होने के कारण हमें अपने कार्यालयों में शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करना चाहिए । आज कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं जिनसे टायपिंग, अनुवाद आदि आसानी से किए जा सकते हैं । अतः आप सभी अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें ताकि रायपुर मंडल राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में भी सदैव आगे बना रहे।मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नराकास, रायपुर को मध्य क्षेत्र के छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश राज्यों में स्थित कुल 57 नराकास में से नराकास राजभाषा सम्मान का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपलब्धियों का यह क्रम निरंतर बना रहेगा।

आरंग में 14 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन

जनता को मोदी की गारंटी और सुशासन का लाभ : साव

रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को आरंग में चार नगरीय निकायों में 14 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आरंग नगर पालिका में तीन करोड़ दस लाख रुपए के 13, मंदिरहसौद नगर पालिका में 50 लाख 44 हजार रुपए के छह, चंदखुरी नगर पंचायत में दो करोड़ आठ लाख रुपए के सात और समोदा नगर पंचायत में 49 लाख 18 हजार रुपए के एक कार्य का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री साव ने आरंग नगर पालिका में दो करोड़ 74 लाख रुपए के 26, मंदिरहसौद नगर पालिका में दो करोड़ 55 लाख 47 हजार रुपए के 37, चंदखुरी नगर पंचायत में एक करोड़ 76 लाख रुपए के दस और समोदा नगर पंचायत में एक करोड़ 12 लाख रुपए के 15 कार्यों का भूमिपूजन भी किया। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब और लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मोदी की गारंटी और सुशासन लेकर आई है। आरंग क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में आरंग विकासखंड के चार नगरीय निकायों चंदखुरी, समोदा, आरंग और मंदिरहसौद में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कुल 174 करोड़ 72 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्र में विकास के ये कार्य आगे भी जारी रहेंगे।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में क्षेत्र के शहरों और गांवों के विकास में तेजी आई है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सक्रियता से काम कर रही है।

अवैध प्लाटिंग पर तेज होंगी कार्रवाई कलेक्टर-एसएसपी ने दिए निर्देश

रायपुर । रायपुर जिले में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और तेजी से की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सोमवार को समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में अवैध प्लाटिंग के मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है। उन्होंने पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों सहित तहसीलदारों और अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर पैनी निगाह रखने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व एवं निगम के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी संबंधित क्षेत्र पर नजर रखें। जहां पर भी अतिक्रमण या अवैध प्लॉटिंग होता दिखे उसे प्रारंभिक मे ही रोक लिया जाए। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने ज़िले के नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकायों में अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पुलिस, राजस्व और नगर निगम से समन्वय स्थापित कर तत्काल निराकरण करने निर्देश दिया। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के पूर्व पुलिस को अवश्य सूचना देने को भी कहा। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएं। सभी ब्लॉकों में ई-केवाईसी के कार्यों में प्रगति लाई जाएं और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजी जाएं। बैठक में कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.